हांगकांग से दिल्ली आई फ्लाइट में लगी आग, बाल-बाल बचे यात्री

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोकशक्ति

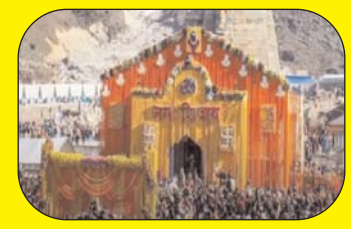

चारधाम यात्रा पर पहुंचे 39 लाख से अधिक श्रद्धालु, बना अनोखा रिकॉर्ड

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 210 | रायपुर | बुधवार 23 जुलाई 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

कांवड़ रूट पर यूपी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी अपनी मुहर

कांवड़ यात्रा मार्ग के होटलों ढाबों पर QR कोड जरूरी

नईदिल्ली,एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटल मालिकों को वैधानिक लाइसेंसिंग और पंजीकरण आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस स्तर पर, सभी संबंधित होटल मालिकों को वैधानिक रूप से आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र के आदेश का पालन करना होगा। हम स्पष्ट करते हैं कि हम बहस किए जा रहे मुद्दों पर विचार नहीं कर रहे हैं। आवेदन बंद किया जाता है। क्यूआर कोड अनिवार्यता के मुद्दे पर, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल इस पर विचार नहीं करेगा और कहा कि क्यूआर कोड और इसी तरह के अन्य मुद्दों पर मुख्य याचिका में विचार किया जा सकता है, जो अभी न्यायालय में लंबित है।

अदालत का यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को

चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित खाद्य स्टॉल मालिकों को अपनी दुकानों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करने, अपनी पहचान और अन्य जानकारियां बताने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वह होटल या ढाबा मालिक का नाम और क्यूआर कोड प्रदर्शित करने संबंधी अन्य मुद्दों पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि मंगलवार कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है।

पीठ ने कहा कि हमें बताया गया है कि आज यात्रा का आखिरी दिन है। वैसे भी, निकट भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना है। इसलिए, इस समय हम केवल यह आदेश पारित करेंगे कि सभी संबंधित होटल मालिक वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने के आदेश का पालन करें।

शीर्ष अदालत शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

199 करोड़ रुपये की आयकर मांग पर कांग्रेस को बड़ा झटका, ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दी अपील

एजेंसी

कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने वर्ष 2017-18 के लिए कर मांग के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी। पार्टी ने आयकर विभाग के उस नोटिस का विरोध किया था जिसमें उसे 199 करोड़ रुपये से अधिक की आय पर कर चुकाने को कहा गया था। कांग्रेस का दावा था कि यह राशि दान से आई है और इसे कर से मुक्त रखा जाना चाहिए। हालाँकि, पार्टी निर्धारित तिथि तक अपना कर रिटर्न दाखिल करने में विफल रही। आयकर न्यायाधिकरण ने कर अधिकारियों के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि पार्टी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त दान पर आयकर का भुगतान करना होगा।

कांग्रेस पार्टी ने 2 फ़रवरी, 2019 को अपना आयकर दाखिल किया और आयकर अधिनियम की धारा 13ए के तहत 199.15 करोड़ रुपये की छूट का दावा करने के बाद शून्य आय घोषित की।

मोदी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर दी प्रतिक्रिया

धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर संसद में हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित

नई दिल्ली : एजेंसी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। धनखड़ ने सोमवार शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने इस्तीफा पत्र में कहा था, 'मैं अपनी सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टरों की सलाह मानने के लिए तुरंत प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहा हूं।' उन्होंने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 67(ए) का हवाला दिया।

वहीं मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में मंगलवार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रश्नकाल के दौरान किसानों के सवालों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने विपक्ष से इमोशनल अपील करते हुए कहा कि वे किसानों और गांव-गरीब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।' पीएम मोदी ने धनखड़ के लंबे सार्वजनिक जीवन और उनकी सेवाओं की सराहना की।

से जुड़े मुद्दों पर चर्चा को बाधित न करें। शिवराज ने कहा कि आज किसानों का दिन और 20 में से 11 सवाल किसानों के हैं। उन्होंने विपक्ष से सदन में किसानों के सवाल उठने देने की अपील की। हालांकि, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में अपने बयान में कहा, 'आज किसानों का दिन है, गांव-गरीब का दिन है। 20 में से 11 सवाल किसानों के हैं। मेरी विपक्ष से प्रार्थना है कि किसानों और किसान कल्याण की चर्चा होने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आज प्रश्नकाल में 20 में से 11 सवाल किसानों, गरीबों और गांवों के हैं। इसलिए मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि किसानों के सवालों को उठने दें। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसदों के सवालों का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजनाएं भी रखना चाहते हैं।'

'विपक्ष महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं होने दे रहा'

शिवराज सिंह चौहान ने ङ्क पर कहा, 'आज संसद में कृषि और किसान तथा ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा होनी थी। प्रश्नकाल में 11 सवाल किसानों और गांव के थे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष अनावश्यक हंगामा कर इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं होने दे रहा है। संसद लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा ही लोकतंत्र के प्राण हैं।

भूपेश के पुत्र चैतन्य बघेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

रायपुर लोकशक्ति

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर की विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब वे 4 अगस्त तक जेल में रहेंगे।

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड ली गई थी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

ईडी के अनुसार, चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये की अवैध आय (POC) रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाने का आरोप है। ईडी ने दावा किया है कि चैतन्य ने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट में फर्जी फ्लैट खरीद के जरिए रकम को सफेद करने की कोशिश की।

'राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025' का अनावरण करेंगे गृहमंत्री अमित शाह

एजेंसी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 24 जुलाई 2025 को अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारिता नीति के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के सदस्य, सभी राष्ट्रीय सहकारी संघों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम , राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद और वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

नई सहकारिता नीति 2025-45 तक आगामी दो दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

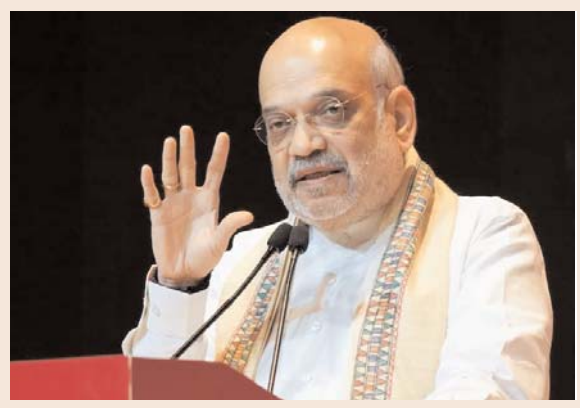

जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में, नई सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और आधुनिक बनाने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर एक रोडमैप बनाकर सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करना है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाने, उनका पेशेवर तरीके से प्रबंधन करने, उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित करने में सक्षम बनना है। पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तर की समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की है।

इससे पहले वर्ष 2002 में देश की पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की गई थी, जिसमें सहकारी संस्थाओं की आर्थिक गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक आधारभूत रूपरेखा दी गई थी। पिछले 20 वर्षों में वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण समाज, देश और विश्व में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए नई नीति बनाना आवश्यक हो गया था, ताकि सहकारी संस्थाओं को वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अधिक सक्रिय और उपयोगी बनाया जा सके और ''विकसित भारत 2047'' के लक्ष्य को हासिल करने में सहकारिता क्षेत्र की भूमिका मजबूत हो सके।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2025 तक बढ़ी

नई दिल्ली.

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.08.2025 तक बढ़ा दी गई है. आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https//awards.gov.in पर 01.04.2025 से शुरू हो चुकी है. यह पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जो बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्तर पर मान्यता के योग्य है. पांच वर्ष से अधिक 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा (31 जुलाई, 2025 तक) जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, पुरस्कार के लिए पात्र है।

मिग-21 फाइटर जेट को हटाएगी वायुसेना

एजेंसी

भारतीय वायुसेना इस साल सितंबर तक अपने पुराने हो चुके मिग-21 लड़ाकू विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटा देगी। इस विमान का संचालन करने वाली स्क्वाड्रन वर्तमान में राजस्थान के नाल एयरबेस पर हैं। इन विमानों की जगह स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस मार्क 1A लेंगे। रक्षा अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। मिग-21 लड़ाकू विमान दशकों से भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार हादसों और पुराने पड़ जाने के कारण इन्हें सेवा से हटाने का फैसला लिया गया है। मिग-21 को

÷उड़ता ताबूत÷ भी कहा जाने लगा, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में इससे जुड़े कई हादसे हुए हैं, जिनमें कई पायलटों की जान गई है। मिग- 21 के रिटायर होने के बाद इसकी जगह स्वदेशी तेजस Mark1A लड़ाकू विमान लेंगे।

तेजस की डिलीवरी में देरी होने के कारण मिग- 21 को कई बार जीवनकाल में बढ़ाकर उड़ान में बनाए रखा गया।

तेजस Mark-1 हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित किया गया है। यह 4.5 जनरेशन का मल्टी-रोल फाइटर जेट है। इसमें कई आधुनिक उपकरण शामिल हैं, जिनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्केन्ड ऐरे रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR) मिसाइल क्षमता और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट शामिल हैं।

देश

भारत ने चीन को साफ और स्पष्ट संकेत दे दिया मोदी कर सकते हैं इस बिल्डिंग का उद्घाटन

भारत ने मालदीव के रक्षा मंत्रालय का नया भवन बनवाया

एजेंसी

मालदीव में स्थित रक्षा मंत्रालय भवन को आधुनिक तकनीक, ऊर्जा दक्षता और हरित निर्माण की अवधारणा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भवन में अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और रक्षा प्रबंधन के अनुकूल तकनीकी सुविधाएं शामिल हैं।

भारत और मालदीव के बीच संबंधों का ऐतिहासिक आधार हाल में कई उतारों को देखने के बाद अब चढ़ाव की राह पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत भारत ने मालदीव के साथ रक्षा, अवसंरचना और आर्थिक सहयोग को नई ऊँचाई दी है। इसी कड़ी में भारत सरकार के सहयोग से मालदीव के

रक्षा मंत्रालय का नया भवन तैयार हुआ है, जो केवल एक इमारत नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच रक्षा और कूटनीतिक संबंधों के सुदृढ़ भविष्य का प्रतीक है।

माले में स्थित रक्षा मंत्रालय भवन को आधुनिक तकनीक, ऊर्जा दक्षता और हरित निर्माण की अवधारणा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। भवन में अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और रक्षा प्रबंधन के अनुकूल तकनीकी सुविधाएं शामिल हैं। हम आपको बता दें कि भारत ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी परामर्श और निर्माण विशेषज्ञता उपलब्ध करायी।

हम आपको बता दें कि मालदीव हिंद महासागर में भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है।

उसकी रक्षा क्षमताओं का सशक्त होना भारत के लिए भी जरूरी है क्योंकि इससे समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान और आपदा प्रबंधन में दोनों देशों के बीच समन्वय और मजबूत होगा। यह नया रक्षा मंत्रालय भवन मालदीव की सैन्य तैयारी और संस्थागत मजबूती को नया आधार देगा। हम आपको बता दें कि यह परियोजना भारत की उस भूमिका को भी रेखांकित करती है जिसमें वह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है।

पीएम मोदी प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर ब्रिटेन जाएंगे

एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से ब्रिटेन की अपनी दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। वह प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वह विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकें करेंगे और व्यापार समझौते, द्विपक्षीय संबंधों जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कल, 23 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ चर्चा के लिए ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर जाएँगे। वह राजा चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात करेंगे। भारत और ब्रिटेन, दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की भी योजना है। पदभार ग्रहण करने के बाद से यह प्रधानमंत्री की ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी। 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से यह उनकी ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी।

यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौता मीडिया को संबोधित करते हुए, मिसरी ने कहा कि भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से एक-दूसरे के निकट संपर्क में हैं। ÷छह मई को प्रधानमंत्री मोदी और यूके के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौते और अन्य मुद्दों पर बातचीत पूरी कर ली है। तब से, दोनों पक्ष एक-दूसरे के बहुत निकट संपर्क में हैं... हम आपको उचित समय पर इससे संबंधित अंतिम विवरण से अवगत कराएँगे।

प्रधानमंत्री मोदी मालदीव का दौरा करेंगे - अपनी दो देशों की यात्रा के ब्रिटेन चरण के समापन के बाद, प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के लिए रवाना होंगे। वह 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में 'मुख्य अतिथि' होंगे। मिसरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा 25 और 26 जुलाई को होगी।

वह मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं... इस अवसर पर, प्रधानमंत्री मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे... यह प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी, और नवंबर 2023 में पदभार ग्रहण करने के बाद से राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू द्वारा आयोजित किसी शासनाध्यक्ष की पहली राजकीय यात्रा होगी।

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता क्रमबद्धता से जारी

एजेंसी

नई दिल्ली भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत मार्च 2025 में शुरू की गई थी और अब तक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है। यह जानकारी मंगलवार को संसद को दी गई। इसी प्रकार, प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच अब तक बारह दौर की वार्ता हो चुकी है। अंतिम दौर 7-11 जुलाई को ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था।

वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, ÷भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता मार्च 2025 में शुरू की गई थी। वार्ता के पांच दौर हो चुके हैं, जिनमें से अंतिम वार्ता 14-18 जुलाई को वाशिंगटन में हुई थी।÷

एक अलग प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में बौद्धिक संपदा (आईपी) फाइलिंग 2020-21 में 4,77,533 से 44 प्रतिशत बढ़कर 2024-25 में 6,89,991 हो गई है। सबसे अधिक वृद्धि भौगोलिक संकेत (जीआई) में 380 प्रतिशत की वृद्धि के साथ देखी गई, इसके बाद डिजाइन (266 प्रतिशत), पेटेंट (180 प्रतिशत), कॉपीराइट (83 प्रतिशत), ट्रेडमार्क (28 प्रतिशत) और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन (एसआईसीएलडी) में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हस्तशिल्प, कृषि और खाद्य जैसे क्षेत्रों में अब तक 697 जीआई पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।

भूपेश के बेटे कौन से पद पर है जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही

कवर्धा, । भ्रष्टाचारियों को बचाने प्रदेश की जनता को परेशान किया जा रहा है इसे कहते है चोरी ऊपर से सीना जोरी भाजपा ने पत्रकार वार्ता में किया कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश जारी किए,कोयला आबंटन और पेड़ों की कटाई के भूपेश बघेल सरकार के कई दस्तावेज भूपेश बघेल झूठ की फैक्ट्री, कोयला आबंटन के लिए कई पत्र लिखे ,परमिशन दिलवाई। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज जिला भाजपा कार्यालय में आहूत संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस बताएं कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल कांग्रेस के किस पद पर है। जिस व्यक्ति का कांग्रेस में कोई पद नहीं उस व्यक्ति के लिए पूरी कांग्रेस प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, इसका साफमतलब है भूपेश बघेल ने पूरी कांग्रेस को पुत्र मोह में झोंक दिया है।

जिला भाजपा कार्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण प्रेस में जिला उपाध्यक्ष जसविंदर बग्गा, महामंत्री संतोष पटेल , जिला पंचायत सदस्य डॉ बीरेंद्र साहू, परेटन वर्मा, श्रीकांत उपाध्याय, पन्ना चंद्रवंशी उपस्थित थे। शर्मा ने कहा हमने पहले भी बड़े-बड़े ऐसे उदाहरण देखें हैं जिसमें लोगों ने पुत्र मोह में खुद को भी बर्बाद किया और अपने पूरे साम्राज्य को भी बर्बाद किया, भूपेश बघेल इस दिशा में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल और कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाने पूरे प्रदेश की जनता को परेशान कर रही है और साथ ही उनका आर्थिक रूप से नुकसान भी करने जा रही है जो की प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के झूठ का पर्दापाश हो गया है। भाजपा ने पत्रकार वार्ता में तथ्यों एवं दस्तावेज प्रेजेंटेशन के माध्यम से कांग्रेस के झूठ को एक बार फिर बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चोरी और सीनाजोरी का उदाहरण बार-बार प्रस्तुत कर रही है। आप सबको पता होगा कि अपने शासनकाल के पाँच वर्ष में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को दस जनपथ का चारागाह बना दिया था। शर्मा ने कहा कि शराब घोटाले, कोयला घोटाले, चावल घोटाले, गोठान घोटाले से लेकर पीएससी घोटाले तक में इसने प्रदेश के संसाधनों को जम कर लूटा था, आज इन घोटालों के आरोपी एक एक कर नप रहे हैं। सभी जेल जा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि बेवजह जिस तरह अपराधियों के विरुद्ध हो रही कानून सम्मत कार्रवाई को कहीं और मोड़ा जा रहा है, वह दुर्भाग्यजनक और कांग्रेस में हिप्पोक्रेसी का सबसे बड़ा नमूना है। विजय शर्मा ने कहा कि जब भी आप सभी कॉल ब्लॉक आवंटन और पेड़ कटाई आदि पर सवाल उठाते थे, तो दस जनपथ के दबाव में सीधे तौर पर भूपेश बघेलजी बचाव में आ जाते थे। कहते थे कि कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध करने वाले अपने-अपने घरों की बिजली बंद कर दें। सवाल यह है कि अब जब झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा कर भूपेशजी अपनी कालिख धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वह अपने घर और राजीव भवन की बिजली बंद करेंगे? शर्मा ने कहा कि यह तथ्य है कि न केवल भूपेश बघेल ने कोल ब्लॉक अशोक गहलोत को आवंटित किया था, बल्कि उससे पहले भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में तमाम नियमों को धत्ता बताते हुए छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक आवंटन की राह आसान की थी। उन्होंने कहा कि साल 2010 में केन्द्र में काँग्रेस की सरकार थी, तब कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हसदेव अरण्य को पूरी तरह से नो-गो जोन घोषित किया गया था। उसे कांग्रेस नीत सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने ही सबसे पहले गो एरिया घोषित किया था। शर्मा ने कहा कि 23 जून 2011 को केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रहते ही तारा परसा ईस्ट और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव दिया गया। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त अडानी को दो बड़ी खदानों गारे पेलमा सेक्टर-2 और राजस्थान में केते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर बनाया गया।

इसी तरह भूपेश बघेलजी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिफारिश भेजी। शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारे पेलमा सेक्टर-2, मांड-रायगढ़ कोलफील्ड के लिए हुआ समझौता भी सबके सामने है। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री रहते ही कांग्रेस सरकार द्वारा वन स्वीकृति स्टेज-1 और 23 जनवरी 2023 को वन स्वीकृति स्टेज-2 के लिए सिफारिश भेजी गई। शर्मा ने कहा कि महाजेंको कोल फील्ड की स्वीकृति में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संलिप्तता को लेकर तब अनेक अखबारों ने समाचार भी प्रकाशित किए थे। 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के रहते राजस्थान को कोल माइंस का आबंटन किया था।

भाजपा ने कांग्रेस से सवाल किया कि:- क्या वह मनमोहन सिंह सरकार के समय हुए निर्णयों के लिए आज माफ़ी मांगेंगे? क्या भूपेश बघेल यह घोषणा करेंगे कि अब कांग्रेस कभी बिजली का उपयोग नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं यह कह चुके हैं कि विरोध करने वाले अपने घर की बिजली बंद कर दें।

कलेक्टर की पहल जनसुनवाई अब होगी और भी सुगम

कार्यालय कलेक्टर में 'जनदर्शन डेस्क' की शुरुआत

सोमवार से शुक्रवार तक, तक संचालित होगा

धमतरी । जनसमस्याओं के त्वरित समाधान और नागरिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर आज अपर कलेक्टर श्रीमती रीता यादव ने आज कलेक्टर कार्यालय में फीता काटकर 'जनदर्शन डेस्क' का शुभारंभ किया। यह डेस्क अब सप्ताह के पाँच कार्यदिवस ङ्क सोमवार से शुक्रवार तक, प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा। इसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं, शिकायतें और आवेदनपत्र सीधे डेस्क में कर सकेंगे। अपर कलेक्टर श्रीमती यादव ने बताया कि अब जनदर्शन कार्यक्रम केवल हर सोमवार तक सीमित न होकर नियमित रूप से सुगम प्रक्रिया के तहत चलेगा। इससे आमजन की समस्याएं शीघ्रता से संज्ञान में लाई जा सकेंगी और समाधान की दिशा में समयबद्ध कार्रवाई संभव हो पाएगी। उन्होंने बताया कि डेस्क के प्रभावी संचालन हेतु एक नोडल अधिकारी के साथ प्रत्येक दिन के लिए दिनवार प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो प्राप्त आवेदनों का संकलन और प्राथमिक स्तर पर परीक्षण सुनिश्चित करेंगे। यह व्यवस्था प्रशासन को जन अपेक्षाओं से जोड़े रखने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। जनदर्शन डेस्क में पहला आवेदन बिसौहा राम साहू से प्राप्त हुआ । उन्होंने अपने खेत में फलदार पौधे लगाने उसकी सुरक्षा हेतु काँटेदार तार की फेंसिंग हेतु आर्थिक मदद का मांगी है ।

भूपेश बघेल के साथ वाली अपनी तस्वीर दिखाकर बेरोजगारों से सरपंच पति ने ठग लिए 20 लाख रुपए

नौकरी दिलाने के नाम पर अपनाया ठगी का अनूठा तरीका

सांई ट्रस्ट में नौकरी का झांसा, बस्तर के बेरोजगारों को लगाया चूना =

जगदलपुर । बस्तर जिले में ठगी का अनूठा मामला सामने आया है। एक सरपंच पति ने भूपेश बघेल के साथ वाली अपनी तस्वीर दिखाकर बस्तर के बेरोजगार युवाओं को बड़ा चूना लगा दिया है। यह शख्स भूपेश बघेल और अपने तस्वीर दिखाकर बेरोजगारों को जाल में फंसा लिया और उन्हें नौकरीदिलाने का झांसा देकर उनसे 20 लाख रुपए ऐंठ लिए। सीमावर्ती राज्य ओडिशा में पंजीकृत सांई ट्रस्ट नाम से संचालित संस्थान में नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर जिला समन्वयक पद पर कार्यरत सरपंच पति सोनसिंह मौर्य ने जिले के 7 विकासखंडों के दर्जनों बेरोजगार युवाओं से 20 लाख से अधिक की राशि की ठगी की है। पीड़ित युवकों ने इस मामले की शिकायत बस्तर कलेक्टर और एसपी से कर उचित कार्रवाई करते हुए राशि दिलाने की गुहार लगाने वाले हैं। दर्जनों युवाओं को इन भारी भरकम वेतन दिलाने का प्रलोभन दिया गया था। अब वेतन तो क्या इन बेरोजगारों को स्वयं की रकम वापसी के लिए तथाकथित जिला समन्वयक के दरभा विकासखंड स्थित गृहग्राम मंगनार के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बेरोजगारों का राशि वापस मिलने की चिंता सता रही है। ठगी का का शिकार हुए युवाओं ने बताया कि जिले के दरभा विकासखंड के सोनसिंह मौर्य जो सरपंच पति हैं, ने वर्ष 2021-22 में विभिन्न ब्लॉक के युवाओं से संपर्क साधा और उन्हें ओड़िशा की सांई ट्रस्ट नामक संस्था में नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया था। मौर्य ने बेरोजगार युवाओं को बताया था का संस्था का मुख्य कार्यालय ओड़िशा के बिंदोपाड़ा, राजसुनखाला, नयाधर में है और यह पंजीकृत संस्था है। जिसका पंजीयन क्रमांक 41131903998 है। सोनसिंह मौर्य स्वयं को संस्था का बस्तर जिला प्रमुख बताता था। संस्था के ब्लॉक समन्वयक पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 25 से अधिक युवाओं से 50-50 हजार रूपये की वसूली की गई थी। वहीं ग्राम पंचायत समन्वयक के पद पर नौकरी दिलाने 5 से 10 हजार उगाही की गई थी। युवाओं ने बताया कि इस तरह दर्जनों युवाओं से 20 लाख से अधिक की ठगी की गई है।

बेरोजगारों ने खाते में भेजी रकम

पीड़ित नरसिंह ध्रुव, महेंद्र कश्यप, जगदीश कश्यप, गोविंद बिसाई, सुभाष बघेल, रेणुका कश्यप, बलीराम बघेल सहित अन्य युवकों ने बताया कि सोनसिंह मौर्य के आईसीआईसीआई बैंक के खाता क्रमांक 5986101001275 में हमने राशि भेजी थी। कई युवकों ने 9770705179 के मोबाईल नंबर पर राशि ट्रांसफर की है।

छत्तीसगढ़ी फिल्म माटी का प्रदर्शन 31 अक्टूबर को होगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल की धरती जहां घने जंगलों की छांव हैं। आदिवासी संस्कृति की गूंज है और साथ ही जारी है जल जंगल जमीन के नाम पर रक्तपात और सम्पदाओं की लूट है। बस्तर के जंगलों में उपजी प्रेम और हिंसा की कहानी इन्ही जटिल परिस्थितियों और द्वंद्व के बीच जन्म लेती है। छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म माटी की कहानी। जब बंदूक की भाषा में संवाद होने लगे तब प्रेम सबसे बड़ा प्रतिरोध बन जाता है। यह फिल्म एक प्रेम कहानी ही नहीं बल्कि बस्तर की सामाजिक और राजनीतिक एवं मानवीय त्रासदी का जीवंत चित्रण है। उक्त जानकारी प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में फिल्म के पटकथा छायांकन सम्पादन एवं निर्देशित करने वाले अविनाश प्रसाद फिल्म के निर्माता सतीश कौशिक ने दी। फिल्म का प्रदर्शन 31 अक्टूबर को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में एक साथ किया जायेगा। पत्रकार वार्ता में अविनाश प्रसाद ने बताया कि 25 मई 2013 को जीरमघाटी में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की हत्या करने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों ने फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लिया है। फिल्म की शूटिंग सुकमा जिले के दोरनापाल से जगरगुंडा मार्ग में सघन वन क्षेत्रों में की गई है। उक्त क्षेत्र पुलिस प्रशासन की मान्यता के अनुसार धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। पत्रकार वार्ता में सम्पत झा, मनोज पाण्डे, संतोष दानी, यशपाल ठाकुर, दिलीप पाण्डेय, दिग्गविजय वर्मा, भूमिका साहा, राकेश यादव, रीना बघेल, सविता रामटेके, नीलिमादास मानीकपुरी, अमित प्रधान , नीरज वर्मा सहित अन्य कलाकार मौजूद थे।

रेत का भाव आसमान छू रहा, भवन बनाने वाले परेशान

ईटें का भी रेट बढ़ा, रेत का पारागांव, महासमुंद में अवैध भंडारण

रायपुर । बरसात लगते ही राजधानी में रेत और ईटें का भाव आसमान छू रहा है जिसके कारण भवन निर्माता काफी परेशान है। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही भी अपना काम रोकने के लिए मजबूर है। बड़े ठेकेदारों एवं आपूर्ति कर्ताओं ने राजधानी के विभिन्न घाटों के पास रेत का भंडारण कर लिया है जिससे वे लाखों की कमाई कर रहे है।

मिली जानकारी के अनुसार राजधानी में इस समय मोटा रेत तथा बारिक रेत का भाव दस हजार रुपये हाइवा से बढ़कर 24 हजार रुपये प्रति हाइवा हो गया है जिसमें 250 फीट रेती आती है। भवन निर्माण आपूर्ति कर्ताओं का कहना है कि बड़े ठेकेदारों ने सरपंच तथा खनिज अधिकारियों से सांठगांठ कर ग्राम पारा गांव जौंदी जौंदा तथा महासमुंद के पास भंडारण कर लिया है जिसे वे बेच रहे हैं। बरसात लगते ही नदियों में जल स्तर बढ़ जाता है इसलिए गर्मी में रेत का भंडारण कर लिया जाता है। ईटें का रेट दो हजार नग प्रति ट्राली 11 सौ से बढ़कर 15 सौ रुपये हो गया है। भवन निर्माण में उपयोग में आने वाले सीमेंट का आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इस समय सभी सीमेंट संयंत्र सीमेंट को बाहर भेज रहे हैं जिसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। ख्यातिनाम ब्रांड के सीमेंट नहीं मिल रहे हैं। इस समय अल्ट्राटेक और एसीसी सीमेंट का मांग ज्यादा है।

भवन निर्माण आपूर्ति कर्ताओं के अनुसार लोहे का रेट सामान्य है यहां पर लोहे का रेट पांच हजार से लेकर 55 सौ प्रति क्विंटल की दर से बढ़ते घटते रहता है। वहीं गिट्टी तथा बजरी का भी रेट घटते बढ़ते रह रहा है।

कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, पर्यावरण प्रेम और हमारी संस्कृति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रीति है : भावना बोहरा

हांथ में कांवड़, मन में छत्तीसगढ़ की सुख-शांति और समृद्धि की भावना के साथ पंडरिया विधायक ने अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक 151 किलोमीटर पदयात्रा के लिए किया प्रस्थान

कवर्धा। अमरकंटक में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सावन माह के द्वितीय सोमवार को माँ नर्मदा मंदिर, अमरकंटक में माँ नर्मदा और नर्मदेश्वर महादेव जी की पूजा-अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख-समृद्धि की कामना की और अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक कांवड़ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसके पूर्व रविवार को भावना बोहरा ने मेला मैदान, नया नगर पालिक परिसर, अमरकंटक में कांवड़ यात्रियों से मुलकात की और उन्हें भोजन परोसकर उनकी सेवा की और भजन संध्या में शामिल हुई। इस दौरान लगभग 3000 से अधिक संख्या में कबीरधाम जिला से पधारे कांवड़ यात्रियों और पंडरिया विधानसभा एवं जिला पदाधिकारी, कार्यकता एवं भक्तजनों ने उत्साह के साथ भजन संध्या में शामिल हुए और हर हर महादेव के नाम से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा।

21 जुलाई सोमवार को भावना बोहरा के साथ लगभग 1000 से अधिक कबीरधाम जिला से पधारे कांवड़ यात्रियों, पंडरिया विधानसभा से आए भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं श्रद्धालुओं ने नर्मदा मंदिर में पूजा-अर्चना की और उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं प्रेषित किया। इस दौरान 300 से अधिक कांवड़ यात्री भावना बोहरा के साथ उनकी इस यात्रा में सहभागी बनें हैं। सभी ने बड़े ही उत्साह और उर्जा के साथ बोल बम और हर हर महादेव के नारे के साथ यात्रा की शुरुआत करते हुए जंगलों के रास्ते छत्तीसगढ़ वासियों एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली के संकल्प के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। यात्रा के प्रथम नर्मदा मंदिर, अमरकंटक से लम्हनी तक यात्रा तय की जाएगी और मंगलवार को पुनः यात्रा आगे बढ़ेगी। 21 जुलाई से प्रारंभ यह यात्रा 27 जुलाई को भोरमदेव मंदिर पहुंचेगी और भावना बोहरा एवं उनके साथ इस यात्रा से जुड़े सभी कांवड़ यात्री एवं भक्तजन डोंगरिया महादेव और भोरमदेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक करेंगे। इस अवसर पर भावना बोहरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों और हमारे प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की मेरी इस संकल्प यात्रा में सहभागी बनें सभी कांवड़ यात्रियों, भक्तजनों और कबीरधाम जिला एवं पंडरिया विधानसभा के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस यात्रा में शामिल सभी का उत्साह एवं भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था और विश्वास एक नई उर्जा देने वाला है।

गौवंश तस्करों के कब्जे से 83 गौ वंश पशु बरामद, जांच में जुटी पुलिस

तेलंगाना राज्य के तस्करों द्वारा छ0ग0 मिनकापल्ली जंगल रास्ते से

बीजापुर । गौवंशी पशुओं को हांककर एटुनगरम, तेलंगाना की ओर ले जाते हुए पकड़ा गया। कब्जे से छुड़ाए गये 83 मवेशियों को एसडीएम भोपालपटनम् द्वारा जारी आदेश के परिपालन में ग्राम पंचायत मद्देड़ कांजी हाउस में सुरक्षित रखा गया। थाना मद्देड़ में गौ तस्करों के विरूद्ध छ0ग0 कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत् की गई कार्यवाही। थाना मद्देड़ क्षेत्रान्तर्गत मुखबीर से सूचना मिली की मवेशी तस्करों के द्वारा मिनकापल्ली-तारलागुड़ा के जंगल रास्ते से गौ वंशी पशुओं को हांककर एटुनगरम तेलंगाना राज्य की ओर ले जाया जा रहा है। मुखबीर से मिली सूचना के आधार पर थाना मद्देड़ बल के द्वारा ग्राम मिनकापल्ली के पास जंगल के रास्ते पशुओं को हांककर ले जाते हुए मवेशी तस्करों को पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ पर अपना नाम :-

अरचंच ईसलावत पिता बसरमा उम्र 26 वर्ष जाति बंजारा निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना, रमेश मुनावत उम्र 25 वर्ष निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना, भुक्य पंतलु पिता स्व0 लिंगा उम्र 55 वर्ष निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना, भुक्या मानसिंह पिता स्व0 नंगु उम्र 45 वर्ष निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना, जरपल्ला कमलेश पिता राम उम्र 22 वर्ष जाति बंजारा निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना, दशरथ जरपल्ला पिता रामु उम्र 30 वर्ष जाति बंजारा निवासी डोडला कोत्तुर एटुनगरम, तेलंगाना, अजमेरा रमेश पिता जग्गु उम्र 25 वर्ष जाति बंजारा निवासी रेडडीपल्ली, तेलंगाना , पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों के पास पशु परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। मौके पर गवाहों की उपस्थिति में 83 नग मवेशी बरामद किए गए।

जगदलपुर में आंगनवाड़ी सहायिकाओं और पालना कार्यकर्ताओं के लिए 5 पदों पर निकली भर्ती

2 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

जगदलपुर। एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय जगदलपुर (शहरी) द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पालना के साथ ही सहायिकाओं के रिक्त 5 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र आगामी 02 अगस्त तक किए जा सकते हैं।

परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय जगदलपुर (शहरी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल 5 पद रिक्त हैं, जिनमें 01 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पालना तथा 04 पद आंगनवाड़ी सहायिका के लिए हैं। इनमें गांधी नगर वार्ड में स्थित कलेक्टोरेट परिसर के पालना केंद्र में पालना कार्यकर्ता के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही वीर सावरकर वार्ड, महारानी वार्ड, गुरु गोविंद सिंह वार्ड और राजेंद्र नगर वार्ड सहायिका के एक-एक पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन सीधे एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय जगदलपुर (शहरी) में जमा किए जा सकते हैं। आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा सहायिका अथवा सह-सहायिका अथवा संगणिका को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आवेदिका उस वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है। निवास के प्रमाण के रूप में वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम और संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी संबंधित वार्ड का निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 12वीं बोर्ड उत्तीर्ण तथा आंगनवाड़ी सहायिका पद हेतु 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि शहरी परियोजना में कोई आवेदिका सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ नहीं मिलती है, तो शैक्षिक योग्यता शिथिल कर विचार किया जाएगा। अनुभवी कार्यकर्ता अथवा सहायिका अथवा सह सहायिका और गरीबी रेखा परिवार अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति परिवार की महिला या तलाकशुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। ये पद पूर्णतः मानसेवी तथा अंशकालिक होंगे।

राजधानी में 5 महाविद्यालय संचालित हो रहे प्राथमिक शालाओं में

कुल शासकीय कार्यालयों की संख्या 365 एवं 1439 आंगनबाड़ी संचालित

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा का हाल बेहाल है प्राध्यापकों की कमी एवं भवन विहीन महाविद्यालयों में पढ़ाई की स्थिति बेहद खराब है। राजधानी में कुल आठ कालेज भवनविहिन है वहीं भवन विहिन स्कूलों की संख्या 1439 है।

राजधानी रायपुर में कई स्कूल पहली पाली एवं दूसरी पाली में लगते है वहीं इन शालाओं में महाविद्यालय भी संचालित हो रहे है जिनकी संख्या 4 है। बिरगांव में भी एक प्राथमिक शाला में महाविद्यालय संचालित हो रहा है। वहीं धरसींवा के पास भी एक महाविद्यालय भवनविहीन है। उच्च शिक्षा में प्राध्यापकों की कमी के कारण शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अनुसार रायपुर में कुल 1412 स्कूल है वहीं आंगनबाड़ी 1439 है। जबकि शासकीय कार्यालय 365 है। इनमें से एक कालेज के सामने ही बजट की उपलब्धता है वहीं चार कालेज के पास भूमि उपलब्ध नहीं है जिसके कारण काफी परेशानी हो रही है।

प्राध्यापकों की कमी से जूझ रहे

पूरे प्रदेश में प्राध्यापकों की कमी है। हाल ही में दस वरिष्ठ प्राध्यापकों को प्राचार्य बनाया गया है लेकिन उन्हें रिलीव नहीं किया गया है उच्च शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के पास चला गया है जिसके कारण बीएड डीएड तथा नये विषयों की अनुमति नहीं मिल पा रही है। इस समय उच्च शिक्षा द्वारा संचालित महाविद्यालय दूसरे के माध्यम से चलाए जा रहे है इनमें सिर्फ अतिथि प्राध्यापकों के सहारे अध्यापन कार्य हो रहा है।

गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350 वें शहादत पर्व पर 1000 श्रद्धालु दर्शन सिमरन यात्रा में शामिल होंग: सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा

सिमरन यात्रा 14 नवम्बर से होगी प्रारंभ, 27 को होगा समापन

रायपुर । धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राण न्योछावर करने वाले सिक्खों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को सिक्ख समाज प्रतिवर्ष अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ स्मरण करता है। इस वर्ष उनकी शहादत के 350 वर्ष (शताब्दी) 25 नवंबर 2025 को पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, स्टेशन रोड, रायपुर द्वारा उनके चरण स्पर्श स्थान – धुबरी साहिब, असम – जाकर नमन करने हेतु विशेष ट्रेन द्वारा दर्शन सिमरन यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें 1000 श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। उक्त जानकारी प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में सिक्ख समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा ने दी। पत्रकार वार्ता में सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि धुबरी साहिब असम प्रांत के धुबरी ज़िले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। सिक्ख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ढाका से असम की ओर यात्रा करते हुए 1505 ईस्वी में इस स्थान पर पधारे थे। तत्पश्चात, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी 1669 ईस्वी में यहाँ आए। उनके चरणों से स्पर्शित इस पवित्र भूमि पर भव्य गुरुद्वारा निर्मित है, जहाँ प्रतिवर्ष उनकी शहादत को समर्पित विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं।

सिक्खों के पाँचों तख्त – तख्त नांदेड़ साहिब, तख्त आनंदपुर साहिब, तख्त दमदमा साहिब, अकाल तख्त अमृतसर साहिब, और तख्त पटना साहिब – प्रत्येक सिक्ख की आस्था का केंद्र हैं। हर सिक्ख अपनी प्रतिदिन की अरदास में इन तख्तों को स्मरण करता है और यह इच्छा रखता है कि वह वहाँ जाकर माथा टेक सके।

यह विशेष यात्रा 14 नवम्बर को रायपुर से आरंभ होगी। यह यात्रा पाँचों तख्त साहिबों के दर्शन करते हुए 24 नवम्बर को धुबरी साहिब, असम पहुँचेगी। वहाँ पवित्र स्थल के दर्शन एवं शहादत पर्व के विशेष आयोजन में भाग लेने के उपरांत 27 नवम्बर को यात्रा रायपुर लौटकर पूर्ण होगी।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए न्यू तकनीक आधारित व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया है, जो भारत में पहली बार किसी धार्मिक यात्रा में किया जा रहा है। इसमें वर्चुअल सेवक के माध्यम से समस्त विवरण, व्यवस्था, समय सारिणी, सीटों की संख्या, ऑनलाइन बुकिंग, बुकिंग स्टेटस उपलब्ध रहेगा। साथ ही व्हाट्सएप नंबर 9009118800 विशेष रूप से जारी किया गया है, जिस पर इस यात्रा संबंधी समस्त विवरण उपलब्ध रहेगा। स्पेशल ट्रेन में एक बोगी को विशेष रूप से सजाया जाएगा, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप प्रकाशित रहेगा। यात्रा के दौरान भजन-कीर्तन होता रहेगा। ट्रेन के सभी कोच में स्पीकर लगे रहेंगे, जिससे श्रद्धालु अपनी बर्थ पर बैठे हुए भी भजन-कीर्तन सुन सकें।

पानी, चाय, नाश्ता, लंगर एवं आवश्यक दवाइयों की फर्स्ट एड किट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।

खेल युवाओं में साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प का विकास करते हैं : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री साय वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में हुए शामिल

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज देर शाम राजधानी रायपुर स्थित सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर देश के 28 राज्यों से आए लगभग 1200 प्रतिभागियों और 300 कोचों का भगवान श्रीराम की ननिहाल और माता कौशल्या की पावन धरती छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि यह राज्य का सौभाग्य है कि वाको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग फेडरेशन ने इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ को चुना। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ राज्य की विशेषताओं से अवगत कराते हुए बताया कि यह देश के हृदयस्थल पर स्थित एक छोटा, परंतु अत्यंत समृद्ध प्रदेश है, जिसका 44 प्रतिशत भूभाग सुरम्य वनों से आच्छादित है। यहाँ 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला सघन अबूझमाड़ क्षेत्र है, जहाँ सूर्य की किरणें तक नहीं पहुँचतीं। राज्य में मनोरम जलप्रपात, सुंदर गुफाएँ, समृद्ध खनिज संपदा और सांस्कृतिक विविधता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने देशभर से आए खिलाड़ियों को आग्रहपूर्वक छत्तीसगढ़ घूमने का निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किक बॉक्सिंग जैसे खेल युवाओं में साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक सशक्त स्थान प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफछत्तीसगढ़ को इस भव्य आयोजन के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग हैं, जो केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और समर्पण का भी पाठ सिखाते हैं।

बूँदें बरसें तो उनके संग मुस्कुराएँ, पर सजगता की छतरी

रायपुर। बरसाती बीमारियों उन दिनों को ज़रा याद करिए जब पसीने से तर बतर शरीर पानी कि एक एक बूंद को सोने से सौदा करने को तैयार था। बस एक ही इच्छा थी, मानसून अब और देरी न कर, अब बरस पड़। लू के थपेड़े अब और नहीं सहे जाते। किसी दिन खबर आती है कि इंद्रदेव की कृपा बहुत जल्द। फिर क्या आज का दिन है कि कहीं पर कृपा, कहीं कहर और हम मनुष्यों को देखो, अब भी संतुष्ट नहीं! इस वक्त भी मोलड्डभाव जारी है। ईश्वर सूर्य की एक किरण ज़रा मिल जाए तो इस कीचड़ से तृप्ति मिले!

अब इसमें हमारी ग़लती नहीं है। मानव शरीर की संरचना ही कुछ इस प्रकार हुई है कि प्राकृतिक चयन के क्रमागत विकास में इसे गर्म रक्त वाले जंतु के रूप में चुना गया है अंग्रेजी में क्रमागत इसलिए क्योंकि हमसे नीचे के जीव जैसे मेंढक, मछली, कीड़े आदि भी हैं जो ठंडे खून के प्राणी हैं। बस इसी प्रकृति के चलते बदलाव मनुष्यों को जल्दी नहीं भाता। हमें ढलना पड़ता है, प्रकृति के अनुसार। न ढलने पर हमें तकलीफ होगी। फिर इसे क्रमगत विकास क्यों कहा गया? इससे अच्छे तो हम मेंढक भले। मगर इस बात पर भी गौर करिए कि हमारी तकलीफ हमें ये ज्ञात कराती है कि किन चीज़ों से हमें परहेज करना है। उदाहरण के तौर पर बहुत गर्मी पड़ने पर, शरीर में पानी की कमी होने पर कमज़ोरी लगती है चक्कर आते हैं, इस तकलीफ से आप को एहसास होता है अब इस धूप से बचना होगा। फिर किसी छांव, कूलर या एसी का सहारा लेकर आप अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। मगर क्या मछलियों को ऐसा एहसास हैं। नहीं। तो हां मनुष्यों को ये क्रमगत विकास से मिला एक वरदान है। व्यापक रूप से देखा जाए तो मानव जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रकृति ने ऐसा जाल रचा है कि हर एक मनुष्य इसमें व्यक्तिगत रूप से सहयोग करता है। है न मज़े कि बात।

चूड़ामणी वार्ड में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण किया महापौर ने, लोगों को मिलेगी समस्या से राहत

वार्ड के युवा महिलाओं एवं नन्हीं बालिकाओं को भी किया गया शामिल

रायपुर । नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे सहित नगर निगम सभापति सूर्यकान्त राठौड़, लोक कर्म विभाग अध्यक्ष और शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड क्रमांक 37 के पार्षद दीपक जायसवाल, जोन 7 जोन अध्यक्ष श्वेता विश्वकर्मा, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष मनोज वर्मा, स्वामी आत्मानंद वार्ड के पार्षद आनंद अग्रवाल सहित गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों, आमजनों, बच्चों की उपस्थिति में रायपुर पश्चिम बिधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 7 अंतर्गत शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड क्रमांक 37 क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न 8 कार्यों का 1 करोड़ 8 लाख रूपये की स्वीकृत लागत वाले विभिन्न 8 नवीन विकास कार्यों का एकमुश्त लोकार्पण कर जनता को अनुपम सौगात दी है.आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयोजन में नए विकास कार्यों के लोकार्पण हेतु वार्ड 37 में सभी 8 विभिन्न स्थानों पर नन्ही कन्याओं का हल्दी कुमकुम लगाकर गृह प्रवेश करवाने की तर्ज पर जनता हेतु लोकार्पण किये जाने की पद्धति की चर्चा करते हुए प्रदेश के पूर्व केबिनेट मन्त्री रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने सराहा और कहा कि उन्होंने नन्ही कन्याओं को हल्दी कुमकुम लगाकर गृह प्रवेश करवाने द्वश तर्ज पर लोकार्पण करवाने की पद्धति शासकीय कार्य में आज पहली बार देखी है. लोकार्पण हेतु ऐसी पद्धति नगर पालिक निगम रायपुर का एक सराहनीय कार्य है. महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड में 1 करोड़ 8 लाख के नए विकोस कार्यों की एकमुश्त लोकार्पण सौगातें मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वार्ड पार्षद एवं एमआईसी सदस्य श्री दीपक जायसवाल की सक्रिय और जागरूक कार्यशैली को सराहा. महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने सभी नागरिकों को सावन के पवित्र मास की हार्दिक शुभकामनायें दीं.प्रदेश के पूर्व केबिनेट मन्त्री रायपुर पश्चिम विधायक श्री राजेश मूणत और महापौर मीनल चौबे ने नगर निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, लोक कर्म विभाग अध्यक्ष और शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड क्रमांक 37 के पार्षद श्री दीपक जायसवाल, मगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष श्री मनोज वर्मा, नगर निगम जोन 7 जोन अध्यक्ष श्वेता विश्वकर्मा, स्वामी आत्मानंद वार्ड क्रमांक 38 के पार्षद श्री आनंद अग्रवाल, एमआईसी सदस्य प्रतिनिधि अशोक पाण्डेय, सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री बजरंग खंडेलवाल, नगर निगम जोन 7 जोन कमिश्नर श्री राकेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे सहित गणमान्यजनों, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों, आमजनों, बच्चों की उपस्थिति में रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड क्रमांक 37 अंतर्गत मेघा मारुति के सामने वन्दना ऑटो के बाजू में अधोसंरचना मद अंतर्गत 50 लाख में सामुदायिक भवन निर्माण का फीता काटकर लोकार्पण करते हुए शानदार सौगात दी.

धर्मान्तरण के मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चर्च के सामने बैठकर किया हनुमान चालीसा का पाठ

भिलाई। भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र एक बार फिर धर्मान्तरण का मामला सामने आया है। भिलाई के ढांचाभवन भवन क्षेत्र में सन मैरिज पैलेस के पास स्थित एक चर्च में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब चर्च के अंदर 100 से अधिक लोग प्रार्थना करने पहुंचे थे। तभी अचानक बजरंग दल के लोगो ने चर्च के अंदर प्रदेश भर के लोगो को लाकर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया । वही जब जामुल थाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई । पुलिस चर्च के अंदर बैठे सभी इसाई धर्म अनुयायियों को बाहर निकाला और बस में बैठाकर उन्हें रवाना किया गया। वही बजरंग दल के लोगो ने चर्च के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बजरंग दल ने भी चर्च के पादरियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है ।

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, शासन की पहली प्राथमिकता

आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं ने कहा-प्रभावी कार्ययोजना बनाकर करें काम

रायपुर ।

स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला अस्पताल सुकमा के सभाकक्ष में आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख योजनाओं, उनके लक्ष्यों, प्राप्तियों और कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई।

डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्राथमिकता वाले कार्यों में से एक है और मलेरिया को खत्म करने लिये शासन हर संभव प्रयास कर रही है। मलेरिया पैरासाइट को खत्म करने के लिए शत प्रतिशत जनसंख्या का स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिया कि मलेरिया पॉजिटिव मरीज के ठीक हो जाने के बाद 1 महीने पश्चात फिर से उस मरीज का फॉलो अप करके ब्लड सैंपल लेकर जांच किया जाए। साथ ही छिन्दगढ़ और कोंटा विकासखंड के गांव मलेरिया के अधिक प्रभाव वाले स्थानों में आते हैं, यहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि फील्ड के अधिकारी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र का भ्रमण करें और बुखार से पीड़ित व्यक्ति का मलेरिया जांच भी करना सुनिश्चित करें।

मंत्री करेंगे बस्तर का दौरा – डॉ. शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मलेरिया मुक्त अभियान की तैयारियों और कार्यों का जायजा लेने के लिए बस्तर संभाग का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉस्टल, आश्रम और गांवों में मच्छरदानी के उपयोग को प्रोत्साहित करना जरूरी है। उन्होंने मलेरिया नियंत्रण के लिए फील्ड में जाकर जागरूकता फैलाने और चिकित्सा कार्यों को और अधिक सघन करने के निर्देश दिए। डॉ. शुक्ला ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूरी मेहनत, पारदर्शिता और आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस कार्यवाही जरूरी है।

धान और किसान एक-दूसरे के पर्याय

रायपुर। राज्य सरकार ने बजट में कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जिसका उद्देश्य कृषि समृद्धि को बढ़ावा देना है। वहीं किसानों के 5 एचपी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य के 5.65 लाख भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही दलहन एवं तिलहन फसलों समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 80 करोड़ रुपये तथा फसल बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रुपये और मोटे अनाजों के साथ-साथ दलहन, तिलहन, बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए कृषक समग्र विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सरकार की किसान हितैषी नियत को दर्शाता है। केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 26 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है। इस योजना में किसानों को तीन किश्तों में साल में 6 हजार रूपए की राशि केन्द्र सरकार के द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में दी जा रही है। केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में धान के विपुल उत्पादन को देखते हुए केन्द्रीय पूल में 78 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य दिया है। ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रूपए तक है। फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60 अनुपात 40 है। सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए खरीफवर्ष 2024 में 15.21 लाख किसानों को 6912 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित किया गया था। वर्ष 2025 में किसानों को 7800 करोड़ रूपए कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। किसानों को 11 जुलाई की स्थिति में 5124 करोड़ रूपए कृषि ऋण वितरित किए गए हैं। यह किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम है। छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की गई है। सौर सुजला योजना के माध्यम से सरकार ने दूरस्थ वनांचल में जहां बिजली की सुविधा नहीं है, वहां किसानों के खेतों में भी इस योजना के माध्यम से सौर सुजला सिंचाई पंप स्थापित कर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियां के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फ ोकस है।

कृषि विभाग के बजट में बीते वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 435 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए राज्य के बजट में भी कृषि के साथ-साथ ग्रामीण विकास को फोकस किया गया है। यहां धान और किसान एक-दूसरे के पर्याय है। पिछले वर्ष 149.25 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर राज्य के 25 लाख 48 हजार 798 किसानों से खरीदी की गई है।

प्रदेश में बलरामपुर में सर्वाधिक और बेमेतरा में सबसे कम वर्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 446 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 739 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 241 मिमी वर्षा दर्ज हुई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 438 मिमी, बलौदाबाजार में 439 मिमी, गरियाबंद में 374 मिमी, महासमुंद में 394.5 मिमी और धमतरी में 372.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है।बिलासपुर संभाग में बिलासपुर जिले में 471 मिमी., मुंगेली में 513 मिमी, रायगढ़ में 571 मिमी, जांजगीर-चांपा में 598 मिमी, कोरबा में 517 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 440 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 437 मिमी, सक्ती में 539 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। दुर्ग संभाग में दुर्ग जिले में 368 मिमी, कबीरधाम में 333 मिमी, राजनांदगांव में 361 मिमी, बालोद में 439 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 522 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 311.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है।सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में 351.6 मिमी, सूरजपुर में 569 मिमी, जशपुर में 546 मिमी, कोरिया में 532 मिमी और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 490 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है।बस्तर संभाग में बस्तर जिले में 509 मिमी, कोंडागांव में 315 मिमी, नारायणपुर में 347 मिमी, बीजापुर में 505 मिमी, सुकमा में 303 मिमी, कांकेर में 403 मिमी, दंतेवाड़ा में 425 मिमी और औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।

कई कलेक्टरों पर गिरेगी गाज

रायपुर । प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज निवास स्थित कार्यालय में बैठकर शासकीय कामकाज निपटाया। बताया जाता है कि सत्र एवं जनजागरूकता अभियान के समय जिन कलेक्टरों एवं अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली है उनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

शासकीय प्रवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मानसून सत्र के पहले जनजागरूक अभियान सहित अन्य कामों में काफी व्यस्त हो गये थे। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना भारत माला, मनरेगा तथा महिला बाल विकास में रेडी टू ईट सहित अन्य शिकायतें मिली थी।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

इंडिया गठबंधन को तवज्जो नहीं

बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर इंडिया गठबंधन के विरोध को उच्चतम न्यायालय ने खास तवज्जो नहीं दी है, लेकिन कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग के भी कान उमेठ दिए गए हैं। न्यायालय ने आयोग को इस प्रक्रिया को पूर्ण करने से तो नहीं रोका लेकिन कहा कि किसी मतदाता की नागरिकता की जांच करना आयोग का नहीं अपितु गृह मंत्रालय का काम है। आयोग को इस प्रक्रिया में आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए। पुनरीक्षण के समय पर भी न्यायालय ने सवाल उठाया। राज्य में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले पुनरीक्षण की जरूरत क्या थी। हालांकि एसआईआर को संवैधानिक दायित्व मानते हुए न्यायालय ने आयोग को एसआईआर जारी रखने की अनुमति दी है।

वो परिंदा भी सजर छोड़ चला गया।

जो नसीब में ना था छूटकर चला गया
अफसोस क्या बीच राह में चला गया ।

जिन साखों में पंछी का पुराना घोंसला
वो परिंदा भी अब सजर छोड़ चला गया।

ठोकरें खा कर मिलती अक्सर मंजिल
वो मंजिल क्या सफर छोड़ चला गया।

तेज रोशनी में अक्सर चौन्धियाती है आंखें
वो अंधेरे में ही मंजिल की ओर चला गया।

दो रोटी के लिए पत्थर तोड़ा करता था
क्यों पकवानों की थाली छोड़ चला गया।

निरा अनजान वो शहर की सियासत से
ऐसा क्या हुआ राजपाठ छोड़ चला गया।

- संजीव ठाकुर,

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp

Modimaya_ Vaidik_Netritva

Rashtriya Ekta

DLF-Vadra-Bhrasht Tantra

Silent Assassins Jan11,1966

Accursed & Jihadi Neighbour

बड़ी जीत है द रेजिस्टेंट फ्रंट का आतंकी संगठन घोषित होना

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

पहलगाम में जब आतंकी हमले में निर्दोषों का रक्त बहा, आहें एवं चीखें गूंजी, जिसने न केवल देश एवं दुनिया को झकझोर दिया था, बल्कि यह संकेत भी दे दिया कि आतंकवाद की जड़ें अब भी जीवित हैं और उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और सीमा-पार समर्थन प्राप्त है। लेकिन इस बार एक बड़ा परिवर्तनकारी एवं प्रासंगिक कदम अमेरिका की ओर से सामने आया है, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की मुखौटा इकाई द रेजिस्टेंट फ्रंट (टीआरएफ) को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया, इस तरह टीआरएफ की पहचान और आतंक के विरुद्ध वैश्विक एकजुटता का नया अध्याय लिखा गया है। यह कदम केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि आतंक के विरुद्ध वैश्विक मंच पर एक रणनीतिक संदेश है कि अब छद्म युद्ध और पनपते आतंक के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही का युग आ गया है। अमेरिका का यह कदम भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विदेश मंत्री एस जयशंकर के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास इस बात के द्योतक है कि आतंकवाद से निपटने के मोर्चे पर भारत सफल हो रहा है। अमेरिका के इस फैसले ने न सिर्फटीआरएफके आतंकी चेहरे से बेपर्दा किया है, बल्कि पाकिस्तान की उन नापाक हरकतों को भी बेनकाब कर दिया, जिन्हें वह खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताकर छिपाता आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे भारत-अमेरिका के बीच मजबूत आतंकवाद-रोधी सहयोग का प्रमाण बताया है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग की जरूरत पर बल दिया है।

टीआरएफ दिखने में एक स्थानीय कश्मीरी संगठन होने का भ्रम देता है, लेकिन असल में यह लश्कर-ए-तैयबा और उसके सरगना हाफिज सईद की पुरानी साजिश का नया चेहरा है। पाकिस्तान-समर्थित आतंकी संगठनों को नया नाम एवं नये रूप में प्रस्तुत करना पाक की एक साजिश एवं सोची-समझी रणनीति है, ताकि दुनिया के सामने वह अपने दामन को पाक-साफ दिखा सके। एक और विडम्बनापूर्ण स्थिति यह है कि पाक ने इसे इस तरह पेश किया जैसे यह कश्मीर का स्थानीय संगठन हो। यह जगजाहिर है कि कई बड़े आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती से संचालित किए जा रहे हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिद्दीन प्रमुख हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार ये सवाल उठे और पाक को आतंक पोषित स्वीकार्य किया जाने लगा। उसका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने रणनीति बदली और आतंकी संगठनों के नाम भी बदलने शुरू कर दिए। टीआरएफ इसका एक उदाहरण है। इसका गठन 2019 के अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद हुआ और इसका उद्देश्य भारत में आतंकी घटनाओं को 'स्वदेशी विद्रोह' की आड़ में अंजाम देना है। पहलगाम हमला भारत के उस प्रयास को चुनौती देता है जो वह 'पर्यटन और विकास के माध्यम से कश्मीर को मुख्यधारा में लाने' के लिए कर रहा है। जब भी कश्मीर में शांति की बहार आती है, ऐसे आतंकी संगठन हिंसा का तूफान लेकर आते हैं। टीआरएफ ने सोशल मीडिया, इंटरनेट और कूटनीतिक शब्दजाल का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को 'कश्मीरी प्रतिरोध आंदोलन' के रूप में पेश करने की कोशिश की, जबकि उसके तार रावलपिंडी और आईएसआई के आतंकवाद समर्थन तंत्र से सीधे जुड़े हैं। मगर, अमेरिका की ओर से इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना इस बात का सबूत है कि आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के इरादों को किसी छद्म नाम की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता।

अमेरिका द्वारा टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना भारत की एक बड़ी राजनयिक एवं कूटनीतिक सफलता है। यह दिखाता है कि भारत की तीक्ष्ण एवं ताकतवर विदेश नीति अब केवल घटनाओं की निंदा तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण की रणनीति पर आधारित है। जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्तावों को भी बल देती है। भारत पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध वर्षों से चेतावनी देते हुए दुनिया को आतंकमुक्त बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर विभिन्न देशों को आतंक के खिलाफ एकजुट करने के प्रयास तेज किये हैं। ऐसे में अमेरिका पर भी यह साबित करने का दबाव बना है कि वह आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड न अपनाये। क्योंकि अमेरिका का दोगलापन चर्चा में रहा है, एक तरफ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का दावा करता है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और विश्व बैंक से बड़ी धनराशि कर्ज के रूप में दी जाती है। एक तरफ राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आतंकवाद की नर्सरी चलाने वाले पाकिस्तान को लेकर अपने नरम रुख का इजहार भी करते रहते हैं। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का ढुलमुल रवैया भी हैरान करने वाला है। सवाल यह है कि जब अमेरिका यह मानता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल-पोस रहा है, तो वह वैश्विक संस्थाओं से उसे वित्तीय मदद रोकने की वकालत क्यों नहीं करता है?

ऑपरेशन सिंदूर में पाक को करारी मात देने के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में वातावरण बनाने के लिये तत्पर हुआ। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती देने के लिये ही भारत ने अमरीका समेत 32 देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे। इन देशों को पुख्ता सबूतों के साथ बताया गया कि टीआरएफ पाकिस्तान प्रायोजित लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। संभवतः भारत के यही प्रयास इस संगठन के खिलाफ अमरीका के सख्त फैसले का आधार बनी। अमरीका ने इससे पहले 2001 में भारतीय संसद पर हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित किया था। पाकिस्तान इन दोनों संगठनों की तरह टीआरएफ को भी भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। निश्चित ही अमेरिका की यह ताजा कार्रवाई स्वागतयोग्य है, लेकिन भारत को अब केवल प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कमर कसते हुए प्रक्रिया दिखानी चाहिए। उसे सीमा पार सर्जिकल/ड्रोन स्ट्राइक की नीति को और मजबूत करना चाहिए। आतंकी समर्थकों की फंडिंग रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों की मांग करनी चाहिए। घरेलू स्तर पर खुफिया तंत्र और साइबर निगरानी को और सक्रिय एवं आधुनिक बनाना चाहिए। वैश्विक मंचों पर एफएटीएफ, यूएन, और जी 20 जैसे संगठनों में पाकिस्तान की आतंक-समर्थक भूमिका को बार-बार उजागर करना चाहिए।

आज आवश्यकता है कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक और शांति-प्रिय राष्ट्र एक मंच पर एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टोलरेंस पॉलिसी अपनाएं। किसी भी राष्ट्र को- चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, आतंकियों की शरणस्थली बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करना पहला कदम है, अब इसकी जड़ों को नष्ट करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। पाकिस्तान सरकार, सेना और आतंक के नापाक गठजोड़ पर जब तक सभी देश एकमत नहीं होंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचेगी। सवाल यह भी है कि जब पाकिस्तान आतंकी संगठनों का खुलेआम समर्थन करता रहता है तो उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ग्रे लिस्ट में डालने से परहेज क्यों किया जा रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि अमरीका के ताजा कदम के बाद एफएटीएफ और दूसरी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां टीआरएफ की फंडिंग की जांच करेंगी।

पहलगाम का हमला एक बार फिर हमें चेतावनी देता है कि आतंकवाद केवल सुरक्षा का संकट नहीं, बल्कि सभ्यता, शांति और मानवता का अपमान है। हमें अब शब्दों से आगे बढ़कर संकल्प और कार्यवाही की ओर बढ़ना होगा। भारत को अब केवल प्रतिकार नहीं, बल्कि निर्णायक प्रहार की नीति अपनानी चाहिए ताकि अगली पीढ़ी एक ऐसे भारत में सांस ले सके जहां 'कश्मीर' केवल खूबसूरती का पर्याय हो, आतंक का नहीं। भारत को वैश्विक मंचों पर टीआरएफ को बेनकाब करने की मुहिम जारी रखनी चाहिए, ताकि इस संगठन को फिर पनप उठाने का मौका न मिले।

यह निजी विचार है।

ऐडफैल्सिवैक्स : क्या मलेरिया मुक्त भारत का स्वप्न साकार होने को है?

लेखक :डा मनमोहन प्रकाश, स्वतंत्र पत्रकार

भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में मलेरिया सदियों से जनस्वास्थ्य विभाग को परेशान करने वाली भयावह, जानलेवा और व्यापक रूप से फैलने वाली बीमारी रही है। वर्षा ऋतु के आते ही मच्छरों की बढ़ती संख्या और उनके साथ मलेरिया के मामलों में अचानक वृद्धि, आज भी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जीवन के लिए संकट पैदा करती है। भारतीय वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से मलेरिया मुक्त भारत का स्वप्न देख रहे थे और उसे साकार करने के लिए दिन-रात प्रयास रत थे। अब ऐसा लगता है कि भारत के चिकित्सा वैज्ञानिकों का स्वप्न स्वदेशी वैक्सीन ऐडफैल्सिवैक्स के माध्यम से साकार होने के बहुत करीब है।भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के नेतृत्व में विकसित ऐडफैल्सिवैक्स भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया-रोधी वैक्सीन है। यह वैक्सीन विशेष रूप से प्लाज़्मोडियम फाल्सिपेरम पर प्रभावी है। ज्ञात हो कि यही प्रजाति मलेरिया परजीवी की सबसे घातक प्रजातियों में से एक है क्योंकि यह तेज़ी से रक्त कोशिकाओं व अंगों को प्रभावित करता है, नुक्सान पहुंचाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में विश्वभर में मलेरिया से लगभग 6 लाख 19 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें से अधिकांश मामले अफ्रीका और दक्षिण एशिया से थे। भारत में भी हर वर्ष लगभग 10 लाख मलेरिया के मामले सामने आते हैं, जिनमें फाल्सिपेरम मलेरिया से पीड़ित रोगियों की संख्या सबसे अधिक होती है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐडफैल्सिवैक्स नामक वैक्सीन को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यह न केवल संक्रामक परजीवी को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, अपितु संक्रमण हो जाने की स्थिति में मलेरिया परजीवी के आगे प्रसार को भी वाधित करता है। वास्तव में यह शरीर में एक प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जो भविष्य में भी मलेरिया परजीवी संक्रमण की पुनरावृत्ति को भी टाल सकती है। यही इस वैक्सीन की सबसे बड़ी विशेषता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह वैक्सीन न केवल उपचार है, बल्कि मलेरिया के संक्रमण चक्र को तोड़ने वाला अचूक शस्त्र है तथा 'मेक इन इंडिया अभियान' की एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक उपलब्धि है। अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत को मलेरिया वैक्सीन के लिए विदेशी आपूर्ति या बहुराष्ट्रीय दवाइयों पर निर्भरता से मुक्ति मिले। यह उपलब्धि निश्चित रूप से देश को वैक्सीन विकास में आत्मनिर्भर बनाती है और वैश्विक स्वास्थ्य में योगदान देने की क्षमता भी प्रदान करता है।

ऐडफैल्सिवैक्स की प्री-क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिसमें इसे सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। अब यह मानव परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल) के चरण में प्रवेश कर चुका है, जो आगामी दो वर्षों तक चलेगा। इसमें भी सफलता मिलना लगभग सुनिश्चित है, इंतजार है केवल चिकित्सिय प्रमाणिक आंकड़ों का। यदि इस ट्राइल के परिणाम भी वैज्ञानिकों की अपेक्षा के अनुकूल रहे तो यह वैक्सीन न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में मलेरिया नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल होगा ।

विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि, ÷ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में आज भी मलेरिया गंभीर खतरा बना हुआ है। ऐसे में यह वैक्सीन न केवल चिकित्सा दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है।÷

विश्व स्तर पर मलेरिया के विरुद्ध वैक्सीन विकास के प्रयास कई वर्षों से चल रहे हैं। अफ्रीका में आरटीएस,एस नामक वैक्सीन को कुछ सफलता मिली है, जिसे डब्ल्यूएचओ ने कुछ देशों में उपयोग के लिए अनुशंसित किया है। किंतु वह वैक्सीन भी सीमित प्रभावशीलता के कारण अभी व्यापक समाधान नहीं बन है सकी है। वहीं भारत की ऐडफैल्सिवैक्स को बहुआयामी दृष्टिकोण से डिज़ाइन किया गया है जो न केवल संक्रमण को रोकती है, बल्कि रोग के प्रसार को भी नियंत्रित करती है।भारत की यह उपलब्धि वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के लिए एक संदेश है कि ÷जब विज्ञान, नीति और सामाजिक उद्देश्य एक साथ चलते हैं, तो असंभव प्रतीत होने वाली समस्याओं का समाधान भी संभव हो सकता है÷।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आज़ भारत न केवल वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, बल्कि कई स्वदेशी वैक्सीनों का सफल विकास एवं निर्माण भी कर चुका है। कोविड-19 के दौरान भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सिन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड ने वैश्विक महामारी से लड़ाई में अहम योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, भारत ने रोटोवेक (डायरिया), टाइपबार टीसीवी (टाइफॉइड),सरवावेक (एचपीवीः सर्वाइकल कैंसर), जायकोवी-डी (डीएनए-आधारित कोविड वैक्सीन), इनकोवेक (नेजल कोविड वैक्सीन) और रीवेक-बी (हेपेटाइटिस-बी) जैसी स्वदेशी वैक्सीनें विकसित की हैं। 'वैक्सीन मैत्री' पहल के तहत भारत ने 100 से अधिक देशों को वैक्सीन देकर वैश्विक मानवता का परिचय दिया है।

अतः यह कहना अब अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत मलेरिया के विरुद्ध निर्णायक युद्ध जीतने के बहुत करीब है और बहुत ही शीघ्र 'मलेरिया-मुक्त भारत' का स्वप्न साकार होने वाला है।

यह निजी विचार है।

स्त्रियों के आर्थिक विकास से जुडी राष्ट्र की मुख्य धारा।

महिलाओं का उत्थान सर्वोपरि।

संजीव ठाकुर

भारत में महिलाओं के विकास का अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रश्न स्वतंत्रता एवं भारत की मुक्ति के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ गया हैद्य स्वतंत्र काल से जुड़ी हुई महिला सशक्तिकरण की यात्रा आज तक अनवरत जारी हैद्य आज भी महिलाएं सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी मोर्चों और सवालों पर पुरुषों के समकक्ष संघर्ष करती नजर आ रही हैद्य आज राष्ट्र निर्माण में नारी अपनी भूमिका से न केवल परिचित है बल्कि उसकी गंभीर जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भी तत्पर व सक्षम हैद्य वर्तमान में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैद्य भारत विकास की दर आज बड़ी से बड़ी वैश्विक शक्ति से टक्कर लेने की जद पर हैद्य विकास की गाथा में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही हैद्य अनेक सामाजिक आर्थिक विसंगतियों के बावजूद आज हर मोर्चे पर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती दिखाई दे रही हैद्य यह आत्मविश्वास उन्हें सदियों के संघर्ष के बाद हासिल हुआ है, प्राचीन काल में अपाला तथा गोसा जैसी विदुषी महिलाओं ने अपनी कीर्ति पताका फैलाई थी, भारतीय समाज में उन्हें सम्मान और बराबरी का दर्जा दिया गया है ,परंतु मध्यकाल में भारत अपनी संकुचित एवं संकट दृष्टि का शिकार हो गया था महिलाओं को घर की चारदीवारी में क्या होना पड़ा थाद्य इसी के साथ कैद हो गई थी उनकी योग्यता,ऊर्जा,शक्ति, आकांक्षाएं और व्यक्तित्व विकास की संभावनाएंद्य भारत एवं भारत के बाहर विदेशों में भारतीय मूल की ऐसे सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है उनके नाम की सूची बड़ी लंबी है उनका उल्लेख न करते हुए समग्र रूप से उनका नमन करते हुए यह बताना चाहूंगा कि महिलाएं निरंतर उच्च पदों पर आसीन हो रही है इन सब के साथ सबसे पुराने बजट तथा घर के अर्थशास्त्र को संभालने की भूमिका का भी कुशलतापूर्वक सदियों से प्रबंधन करती आ रही हैद्य इसके साथ ही वे अपनी शैक्षणिक योग्यता में निरंतर सुधार कर रही है जनसंख्या गणना के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं, महिलाएं जहां शिक्षा, प्रशासन,मेडिकल क्षेत्र, इंजीनियरिंग, स्पेस रिसर्च, विज्ञान टेक्नोलॉजी और उद्यानिकी ,एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर और तमाम क्षेत्रों में असाधारण रूप से शिक्षा प्राप्त कर प्रगति कर रही और उच्च पदस्थ होकर कार्यों का कुशलता से संपादन कर रही हैंद्य सामाजिक कुरीतियों के विरोध में समाज को आगाह करने और उसका विरोध करने में भी महिलाएं पीछे नहीं है, फिर चाहे वह शनि सिंगनापुर हाजी अली दरगाह या तीन तलाक के मामले में इनकी सजगता ने सामाजिक परिवर्तन लाया है। सरकार भी इनकी इस भूमिका को स्वीकार करते हुए थल जल और वायु सेना में युद्धक की भूमिका मैं इनकी नियुक्ति कर रही है। हम यदि राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा करें तो पंचायती स्तरों पर महिला प्रधानों ने गंभीर परिवर्तन के प्रयास किए, किंतु हमें यहां हमेशा स्मरण रखना चाहिए की देश के आर्थिक विकास में अभी भी महिलाओं को वह भागीदारी व सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए वह पूर्णरूपेण हकदार है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया की श्रम बल भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी 25त्न से भी कम हो गई है। महिलाओं को अनेक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को समान पदों पर कार्यरत पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है तथा अधिकांश शीर्ष पदों पर पुरुषों का कब्जा है के अलावा दुनिया की सबसे कम तनखा वाली नौकरियों में 60त्न महिलाएं ही हैं। महिलाओं द्वारा अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कार्यस्थल पर कार्य करते हुए देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।इन परिस्थितियों में महिलाओं द्वारा दिए गए सामाजिक आर्थिक विकास के योगदान को पहचानते हुए सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम 2016 तथा यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के माध्यम से अनुकूल वातावरण तथा महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने के कई अच्छे प्रावधान भी उपलब्ध कराए हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अपने आंकड़ों से स्पष्ट करता है की किस प्रकार महिलाओं की श्रमबल में अधिक भागीदारी जीडीपी में अप्रत्याशित वृद्धि करता है। पूरा विश्व इस बात से सहमत है की महिलाएं कोमल है पर कमजोर नहीं एवं शक्ति का नाम ही नारी है। हिंदुस्तान के विकास में सही मायने में यदि 50त्न भागीदारी महिलाओं की हो तो असाधारण क्षमता की धनी महिलाएं इस देश को विश्व के अन्य विकसित देशों में खड़ा कर सकती हैं, जरूरत इनकी शक्ति क्षमता एवं योग्यता को पहचानने की है। 21वीं सदी में विश्व शक्ति रूप भारत के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में महिलाओं का सर्वांगीण विकास को आधार बनाकर आर्थिक महाशक्ति के स्वप्न को साकार किया जा सकता है।

संस्कृत भाषा हमारी विरासत है – संस्कृत भारती

(संस्कृत भारती संगठन का प्रांत कोर कमेटी की बैठक)

रायपुर, लोकशक्ति।

संस्कृत भाषा के संरक्षण व संवर्धन हेतु शिक्षक सदन टैगोर नगर रायपुर में संस्कृत भारती छत्तीसगढ़ की प्रान्त कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संस्कृत सप्ताह आयोजित करने की रणनीति, विद्यालयीन शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन अनुसार छत्तीसगढ़ में संस्कृत शिक्षा पर बल देने पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक मे आगामी समय में छत्तीसगढ़ में संस्कृत शिक्षा की उन्नति हेतु संस्कृत शिक्षकों का विकास खंड, जिला व प्रान्त स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। विद्यालयीन शिक्षा में संस्कृत की अनिवार्यता पर प्रमुखता से बल दिया गया। बैठक में संस्कृत भारती प्रान्ताध्यक्ष सतेन्द्र सिंह सेंगर, प्रांतमंत्री डॉ. दादूभाई त्रिपाठी, संगठन मंत्री हेमन्त साहू, वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉ. बहुरन पटेल, डॉ प्रवीण झाड़ी, डॉ दिव्या देशपांडे, डॉ लूनेश कुमार वर्मा, पूर्णोत्तम साहू, राजेश राजपूत, पारस साहू, चोवा लाल धीवर, शेषनारायण गजेंद्र, थानेश्वर आदि पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।

डॉ. सतेन्द्र सिंह सेंगर एवं डॉ. दादूभाई त्रिपाठी तथा अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने संस्कृत सप्ताह पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने तथा संस्कृत विषय को प्राइमरी शिक्षा मे शामिल करने हेतु एवं गीता, रामायण, महाभारत , वेद, शास्त्रों को पाठ्यक्रम मे शामिल करने हेतु जोर दिया गया।

संस्कृत हमारी विरासत है, इसका प्रचार प्रसार हम सभी का कर्तव्य है। छत्तीसगढ़ मे जन जन तक संस्कृत को पहुँचाने का काम संस्कृत भारती कर रही है। कार्यकर्ताओं का संकल्प है हम सभी मिलकर संस्कृत को हर घर तक लोकप्रिय बनाने का काम करेंगे।

संस्कृत भाषा को बच्चों से लेकर बड़े तक सबके लिए लाभकारी बताया। संस्कृत क्यों आवश्यक है क्योंकि संस्कृत से समृद्धि एवं संस्कार की प्राप्ति होती है। यदि घर मे संस्कृत भाषा का उपयोग होता है तो वहाँ भगवान् की भक्ति के साथ संस्कृत के विविध ग्रंथों का पठन - पाठन होगा जिससे घर के बच्चों मे अच्छे संस्कार आयेंगे और सुखमय जीवन के लिए अच्छे संस्कार का होना परम आवश्यक है। संस्कृत भाषा का मानव जीवन मे उपयोगिता व महत्व पर जोर दिया। उक्त जानकारी संस्कृत भारती रायपुर के प्रचार विभाग से जुड़े पं. चन्द्रभूषण शुक्ला ने दिया।

श्री डेका ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता से नवाचार करने पर बल दिया।

प्रतिभा का अर्थ है व्यावसायिक संसाधन और प्रतिभा एकीकरण और सेतु का अर्थ है पुल

पीआईबी

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यूपीएससी की ÷प्रतिभा सेतु÷ पहल की सराहना की है।

प्रतिभा का अर्थ है ÷व्यावसायिक संसाधन और प्रतिभा एकीकरण÷ और सेतु का अर्थ है ÷पुल÷।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह पहल उन सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए एक सार्थक मंच के रूप में उभर रही है, जो सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम चरण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने और साक्षात्कार में शामिल होने के बावजूद बहुत कम अंतर से अंतिम चयन से वंचित रह जाते हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसे प्रतिभा उपयोग के लिए एक ÷अग्रगामी सोच वाला दृष्टिकोण÷ बताते हुए यह टिप्पणी संघ लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार के साथ बैठक के बाद की। डॉ. अजय कुमार ने उन्हें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के नियोक्ताओं के बीच इस मंच के बढ़ते आकर्षण के बारे में जानकारी दी।

अध्यक्ष के अनुसार, यह पहल - जो मूल रूप से 2018 में शुरू की गई सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना से विकसित हुई है - को सभी ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कई निजी संगठनों ने आयोग से संपर्क करना शुरू कर दिया है ताकि उन अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त की जा सके जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के चरणों में सफल रहे, लेकिन अंततः चयनित नहीं हुए।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभ्यर्थी भी इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि यह उन्हें सिविल सेवा की सीमाओं से बाहर अपने कौशल और ज्ञान को सार्थक करियर विकल्पों में उपयोग करने का एक व्यावहारिक विकल्प प्रदान करता है।

प्रतिभा (व्यावसायिक संसाधन और प्रतिभा एकीकरण) सेतु - भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सेतु है, जो सत्यापित संगठनों को पंजीकरण करने और यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं – जैसे सिविल सेवा, भारतीय वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा आदि – में चयनित नहीं हो पाने वाले उम्मीदवारों के डेटा तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इस पहल से अब तक 113 संगठन जुड़ चुके हैं, और कई अन्य संगठन इस पोर्टल में अच्छी तरह से मूल्यांकित मानव संसाधनों के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में रुचि दिखा रहे हैं।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में वर्ष 2018-2021 के लिए स्काउट्स/गाइड्स/रोवर्स/रेंजर्स पुरस्कार समारोह में.

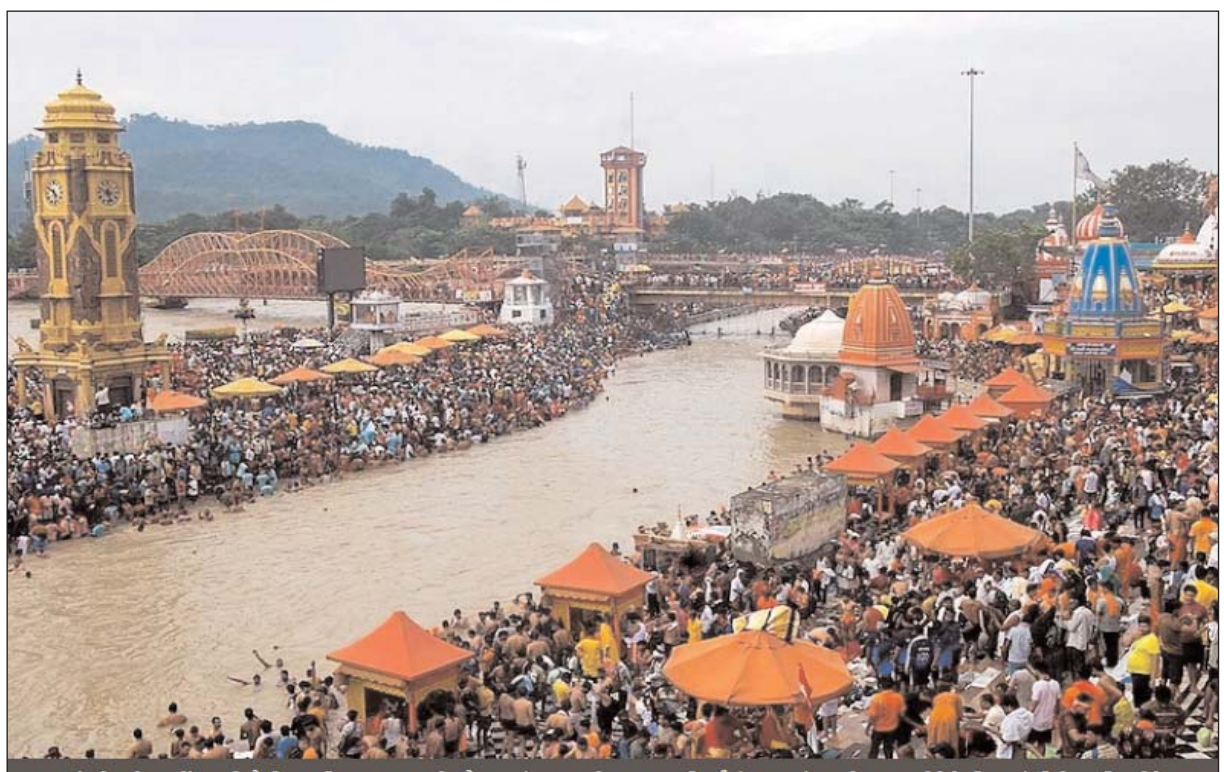

उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा के समापन की पूर्व संध्या पर गंगा नदी का जल लेने के लिए कांवड़िये एकत्रित होते हुए।

मनरेगा के अंतर्गत फर्जी जॉब कार्ड रद्द किए गए

पीआईबी

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत रद्द किए गए फर्जी जॉब कार्डों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है। चूंकि योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, परिचालन दिशा-निर्देशों, वार्षिक मास्टर परिपत्र आदि में उचित कार्यान्वयन के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, इसलिए प्राथमिक रूप से संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को योजना के कार्यान्वयन में किसी भी अनियमितता के मामले में उचित कार्रवाई करनी होती है, जिसमें कानून के अनुसार मामले की गंभीरता के आधार पर जांच और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। मंत्रालय स्तर पर फर्जी जॉब कार्ड जैसे अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओडिशा में सुनवाई और शिविर बैठक का समापन किया

भारत के 144 मामलों की सुनवाई की गई; अधिकार उल्लंघन के तहत पीड़ितों को लगभग 28 लाख रुपये की आर्थिक राहत की अनुशंसा की गई

ओडिशा के विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य की उपस्थिति में पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत लगभग 1 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के 25 मामलों की सुनवाई की गई

पीआईबी – भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आज भुवनेश्वर में अपनी दो दिवसीय ओडिशा खुली सुनवाई और शिविर बैठक का समापन किया। इस दौरान 144 मामलों की सुनवाई की गई और ओडिशा राज्य में मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को लगभग 28 लाख रुपये की राहत राशि देने की अनुशंसा की गई। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वी. रामसुब्रमण्यन, सदस्य न्यायमूर्तियों (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी और श्रीमती विजया भारती सयानी ने महासचिव श्री भरत लाल, रजिस्ट्रार (विधि) जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं की उपस्थिति में मामलों की सुनवाई की गई।

आयोग ने हिरासत में मृत्यु, राज्य द्वारा संचालित गृहों में मृत्यु, आग लगने से अस्पतालों में बच्चों की मृत्यु, डूबने से मृत्यु, आवारा कुत्तों के काटने, बाल तस्करी, बुनियादी मानवीय सुविधाओं से वंचित रखने, दुष्कर्म सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, गुमशुदा व्यक्ति, पुलिस अत्याचार, आत्महत्या से मृत्यु, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करना, बिजली से मृत?यु के मामले आदि सहित विभिन्न मामलों पर विचार किया।

विभिन्न मामलों में उचित निर्देश पारित किए गए, जैसे एक वरिष्ठ जनजातीय महिला को पेंशन, 15,000 रुपये की अंतरिम राहत और अन्य सामाजिक कल्याण लाभ प्रदान करना; कई मामलों में पुलिस जांच में तेजी लाना और न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल करना; तथा एक खतरनाक पटाखा फैक्ट्री में काम करते समय मरने वाले पांच श्रमिकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति देना।

विवाह के 50 वर्ष पूर्ण होने एवं 500 पौधा रोपण किए जाने पर स्वर्ण दम्पत्ति सम्मान

लोकशक्ति संवाददाता - रायपुर

विवाह के 50 वर्ष पूर्ण होने पर परिवार सहित पौधारोपण आयोजन के द्वारा 500 नग पौधा रोपण किए जाने पर , बेलगांव (साजा) निवासी भागवताचार्य पं. कृष्णा प्रसाद शुक्ला व श्रीमती चंद्रावली शुक्ला को छ. ग. प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने स्वर्ण दंपत्ति सम्मान से सम्मानित किया।

पं. शुक्ला इस उम्र मे आज भी 15-20 किलोमीटर रोज पूजा पाठ हेतु आना जाना करते हैं और भागवत, रामायण, गीता आदि की कथा सुनाते हैं। पं. शुक्ला बहुत ही सरल व्यवहार एवं उत्तम व्यक्तित्व के धनी है तथा इनका सादगीपूर्ण जीवन सबके लिए अनुकरनीय है। अभी भी वे घर के छानही में खपरा ठीक करने चढ़ जाते हैं, पैतृक गौ सेवा के लिय घर में रखे गायों के हर तरह की व्यवस्था व सेवा स्वयं अपने हाथों से ही करते हैं।

वहीं श्रीमती चंद्रावली शुक्ला भी अपने बाल्यावस्था जीवन से ही अति संघर्ष करने के बाद भी प्राचीन शिक्षा पद्धति में प्राथमिक कक्षा पास थी। लेकिन विगत 15 सालों से गांव में मितानिन का कार्य , प्रशिक्षण आदि के साथ हाई व हायर सेकंडरी की परीक्षा पास कर समाज सेवा में लगी हुई है। ग्रामीण महिलाओं को स्वास्थ के प्रति जागरूक करती है तथा प्रसव आदि हेतु तत्काल अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कराती है।

6 जुलाई 2025 को 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर पूरे परिवार सहित 50 पौधे खारुन नदी के किनारे एवं विभिन्न जगहों पर व 500 पौधे मंदिर के गांव जामगांव एम में मंदिर के सदस्यों के साथ पौधारोपण किए है। उक्त सम्मान कार्यक्रम रोहणीपुरम तालाब पार भवन में आयोजित हुआ जहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए वाचनालय का उद्घाटन किया गया एवं एक पेड़ माँ के नाम तहत पौधारोपण भी किया गया।

समाज के अध्यक्ष श्रीमती भारती किरण शर्मा सहित अनेक गणमान्य अतिथियों एवं ब्राह्मण समाज के दूर-दूर से आये लोगों की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलित कर आये हुए अतिथियों का स्वागत किया गया फिर विवाह के 50 वर्ष पूर्ण हुए दम्पत्तियों का शाल, श्रीफल, शील्ड एवं एक पौधा भेंट किया गया।

पं. शुक्ला दम्पत्ति महामाया मन्दिर रायपुर के ज्योतिषी एवं भागवताचार्य समाजसेवी पं. मनोज शुक्ला, पं. चन्द्रशेखर शुक्ला, संस्कृत भाषा के प्रचारक पं. चन्द्रभूषण शुक्ला, गायत्री शक्तिपीठ समता कॉलोनी के मीडिया प्रभारी पं. राजेश शुक्ला, श्रीमती ममता पांडेय व श्रीमती माया तिवारी के माता - पिता हैं । इस सम्मान से पूरे परिवार मे हर्ष का वातावरण है एवं सम्मान पश्चात सभी परिवार सरोना स्थित प्राचीन शिव मन्दिर जाकर दर्शन पूजन किये।

अध्यक्ष श्रीमती भारती किरण शर्मा ने बताया कि संगठन के 10 वर्ष में प्रवेश होने के अवसर पर अखण्ड ब्राह्मण समाज द्वारा कई सामाजिक, बौद्धिक गतिविधियों मे शामिल रहा है। इसी तारतम्य मे उक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें संगठन के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

विभिन्न राज्य विधानसभाओं में भाषाई समावेशिता बढ़ाने के लिए ई-विधान ऐप्लिकेशन में प्रौद्योगिकीय विशेषताएं समेकित की गई

पीआईबी। विभिन्न राज्य विधान सभाओं में भाषाई समावेशिता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (एनईवीए) में निम्नलिखित प्रौद्योगिकीय विशेषताएं समे?कित की गई हैंः - भाषिणी के माध्यम से टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट मशीन अनुवाद को एनईवीए सार्वजनिक पोर्टलों (होमपेज और राज्य विधानसभा पोर्टल) को 22 अनुसूचित क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एकीकृत किया गया है, जिससे भाषाई समावेशिता सुनिश्चित हो।

सभी कंटेंट इनपुट, स्टोरेज और रिट्राईवल के लिए यूनिकोड आधारित एनकोडिंग आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है, जिससे ऐप्लिकेशन के कंटेंट मैनेजमेंट सिस?टम के भीतर अंतर-पारस?परिकता सुनिश्चित और बहुभाषायी एक?सेस संभव हो सके।

पत्र सूचना कार्यालय ने 673.94 करोड़ रुपये की कुल लागत परि?यय के साथ एनईवीए परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए निम्नलिखित प्रारूप पर आधारित हैः - पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए वित्तपोषण 90:10 के अनुपात में होगा।

जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल हैं, वहां 100 प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र द्वारा किया जाएगा।

अन्य सभी राज्यों के लिए वित्तपोषण 60:40 के अनुपात में होगा।

कुल 28 राज्य/केंद्र शासित राज्य क्षेत्र विधानमंडलों ने एनईवीए को अपनाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

जून 2025 तक, 19 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल एनईवीए प्लेटफॉर्म के माध्यम से सफलतापूर्वक पूर्ण डिजिटल विधानमंडलों में परिवर्तित हो गए हैं।

संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

मोहड़ रेत मामले को लेकर कांग्रेस का घेराव 24 को

मोहड़ गोलीकांड के मुख्य आरोपी भाजपा का पदाधिकारी संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बसंतपुर थाने का होगा घेराव

राजनांदगांव।

संस्कारधानी शहर के मोहड़ वार्ड नं. 49 में रेत माफ्याओं निर्दोष ग्रामीणों पर लाठीडंडा व बंदूक की नोक पर वारदात करते हुए गोलीकांड जैसी अपराधिक घटना हुए लगभग एक से डेढ़ माह बीत चुकी है किन्तु अब तक मुख्य आरोपी संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिसको लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में गुरूवार 24 जुलाई बसंतपुर थाने का घेराव किया जा रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष श्री छाबड़ा ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जब तक मुख्य सरगना की गिरफ्तारी नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा। कांग्रेस सदैव जनहित की लड़ाई लड़ी है इस घटना के बाद से आज दिनांक तक कांग्रेस लगातार रेत माफ्याओं पर कार्यवाही की मांग कर रहा है। जबकि इसको लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा पुलिस प्रशासन को 08 दिन में अपराधियों कार्यवाही करने का अल्टीमेंटम दिया था नही तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी, उसके बावजूद भी कार्यवाही शून्य है। श्री छाबड़ा ने कहा कि मुख्य सरगना संजय सिंह अभी भी फरार है, रेत माफ्याओं का लिंक सीधा भाजपा नेताओं जुड़ा इस कारण इसे बचाने में लगी है।

चारागाह में हरियाली की ओर कदम : लखाली में हुआ 556 पौधों का मनरेगा से सफल पौधरोपण

जांजगीर-चांपा

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत विकासखण्ड बम्हनीडीह के ग्राम पंचायत लखाली में चारागाह क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण कर हरियाली की नई शुरुआत की गई। इस कार्य के अंतर्गत आम, नीम, जामुन, नींबू एवं अमरूद जैसे 556 पौधों का रोपण किया गया।

ग्राम पंचायत लखाली जिला मुख्यालय से लगभग 32 कि.मी. तथा विकासखण्ड मुख्यालय बम्हनीडीह से 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। मनरेगा के माध्यम से यह परियोजना वर्ष 2025-26 में स्वीकृत हुई है। परियोजना की कुल स्वीकृत राशि 3.127 लाख (मनरेगा मद से) है, जिससे पौधरोपण के साथ जल-संरक्षण एवं संचय से संबंधित गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। तीन वर्षों की इस परियोजना में वर्षवार मानव दिवस सृजन की प्रक्रिया प्रगति पर है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में सीईओ जनपद पंचायत, जनपद सदस्य सचिव, सरपंच, पंचगण, स्व सहायता समूह की दीदियों एवं स्थानीय ग्रामीणजनों की सक्रिय

भागीदारी रही। सभी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इस सामूहिक प्रयास को महत्वपूर्ण कदम बताया। ग्रामीणों ने इस प्रयास को ग्राम के भविष्य के लिए लाभकारी बताया और इसे हरित भविष्य की नींव माना। यह प्रयास न केवल पर्यावरण को समृद्ध करेगा, बल्कि स्थानीय रोज़गार को भी बढ़ावा देगा। आगामी वर्षों में इन पौधों की हरियाली चारागाह को जीवनदान देगी और मवेशियों के लिए भी यह वरदान साबित होगा।

इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। लहिय न कोटि जोग जप साधे - राजेश्री महन्त

द्वितीय सोमवार को शिव दर्शन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए महामंडलेश्वर

जांजगीर चांपा / छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष महामंडलेश्वर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज श्रावण मास के द्वितीय सोमवार को जांजगीर चांपा जिले में विराजित अनेक शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर निर्धारित समय में पहुंचकर भगवान शिव का दुग्धाभिषेक एवं जलाभिषेक कर संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामनाएं की। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि- भगवान शिव शंकर समस्त जीवों के कल्याण कर्ता हैं,इसलिए उनका नाम शिव है। मनुष्य के इच्छाओं की पूर्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा पर आधारित है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि- *इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। लहिय न कोटि जोग जप साधे। अर्थात मनुष्य के द्वारा वांछित कार्यों की पूर्ति भगवान शिव की आराधना के बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता! इसीलिए मनुष्य को वांछित फलों की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजेश्री महन्त जी महाराज ने अपने सहयोगियों सहित शिवरीनारायण में चन्द्रेश्वर महादेव, चंद्रचूड़ महादेव, राम जानकी मंदिर के सामने स्थित शिवाजी, खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव, तुस्मा में जोतगीर बाबा, कीरीत में कीर्तिकेश्वर महादेव, पीथमपुर में कलेश्वर नाथ महादेव, तुर्रीधाम में शिव जी, जैजैपुर में गौरीकन्या महादेव, तथा ओड़ेकेरा में शिव मंदिर, देवपुर में सिद्धनाथ बाबा, बड़गड़ी में सिद्धेश्वरनाथ जी का दर्शन पूजन किया। इस कार्यक्रम में उनके साथ अलग-अलग स्थानों पर सुबोध शुक्ला, गोविंद यादव, कमलेश सिंह,सरदचंद शर्मा, प्रमोद सिंह, रामखिलावन तिवारी, जगदीश यादव, शिव कुमार साहू, जीवनलाल कुंभकार, भुवन दास वैष्णव, शत्रुघ्न दास वैष्णव, तरुण साहू श्रीमती साहू, दिनेश साहू, गजेंद्र दास वैष्णव, रूपेश वैष्णव, सुरेश साहू, श्रीमती सरिता साहू, बसंत पवार, दिलदार खान, संतोष साहू, तेरस राम साहू, सुरेश जयसवाल, भगत राम शर्मा, पुरेंद्र सोनी, भानु चंद्रा, आदित्य जी, रामराज पांडे, हेमंत साहू, सुकृता पटेल, मीडिया प्रभारी निर्मल दास वैष्णव, हर्ष दुबे सहित अनेक गणमान्य नागरिक गण सम्मिलित हुए।

अग्रवाल सम्मेलन के लोग राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन दिए

जांजगीर-चांपा / अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की छत्तीसगढ़ प्रांतीय ईकाई द्वारा माननीय राज्यपाल छ.ग. शासन श्रीमान् रमेन डेका जी से मुलाकात कर मानवता के प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी का जीवन परिचय छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु ज्ञापन दिया गया। राज्यपाल महोदय द्वारा विचार कर लागू करवाने का आश्वासन दिया गयाद्य छत्तीसगढ़ प्रांतीय ईकाई के निम्न पदाधिकारी उपस्थित रहे किशन लाल अग्रवाल, ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, मुरलीधर अग्रवाल, रमेशचन्द्र अग्रवाल (वकील), रमेश कुमार अग्रवाल एवं अशोक गोयल आदि उपस्थित थे । उक्त जानकारी मुरलीधर अग्रवाल (महामंत्री) से मिली द्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती हेतु चयन एवं प्रतिक्षा सूची जारी

जांजगीर-चांपा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जिला स्तर के रिक्त 48 संवर्ग के 148 संविदा पदों की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिसमें 15 संवर्ग के 21 संविदा पद के लिए कौशल परीक्षा आयोजित किया गया था। उक्त संविदा पदों का शैक्षिणक योग्यता, अनुभव अंक एवं कौशल परीक्षा / साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर चयन समिति द्वारा चयन एवं प्रतिक्षा सूची जारी किया गया है। जिसे जिले के वेबसाइट https//jan-jgir-champa.gov.in/ में भी अवलोकन किया जा सकता है एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर चांपा के नोटिस बोर्ड में भी चस्पा किया गया।

धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले दो आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी के विरूद्ध धारा 299 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

जांजगीर चांपा /

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दो आरोपी को नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि समाजिक व्यक्तियों के द्वारा धार्मिक भावना के भगवा ध्वज को रस्सी से पेड़ एवं खंभा में बांधा गया था। इसे अलफ खान ऊर्फ गुड्डा खान निवासी खैरताल एवं शिवकुमार कश्यप के द्वारा दिनांक 20 जुलाई 25 को सुबह धार्मिक भगवा ध्वज को निकाल कर फेंक दिया और भगवा ध्वज बंधा पेड़ को काट दिया जिसकी सूचना रिपोर्ट पर दिनांक 20 जुलाई 25 को थाना नवागढ़ में अपराध क्र. 308/25 धारा 299 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। धार्मिक भावनाओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की मामला को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के प्रकरण में तत्काल कार्यवाही के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जांजगीर विजय कुमार पैकरा के कुशल मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी नवागढ़ निरीक्षक अशोक वैष्णव के नेतृत्व तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनो आरोपियों को पकड़ा । उन्हे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है । उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अशोक वैष्णव थाना प्रभारी नवागढ़, संतोष केरकेट्टा, आर. अमन राजपूत, राजू कश्यप, संजय टंडन एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

कृषकों के फार्मर रजिस्ट्री के लिए 23 से 31 जुलाई तक समितियों में किया जाएगा कैम्प का आयोजन

जांजगीर-चांपा भारत सरकार कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छ.ग. राज्य में एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत कृषक पंजीयन का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 में धान खरीदी कृषक पंजीयन के आधार पर किया जाना है। इसके लिए समितिवार दल गठित की गई है। उक्त गठित दल के माध्यम से कृषकों का फार्मर रजिस्ट्री के लिए सेवा सहकारी समितियों में 23 से 31 जुलाई 2025 तक कैम्प आयोजित कर पंजीयन किया जाएगा।

आगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु आवेदन आमंत्रित*

जांजगीर-चांपा 22 जुलाई 2025/ एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र सत्तीगुड़ी 117 में कार्यकर्ता पद एवं आंगनबाड़ी केन्द्र नगरपंचायत बलौदा वार्ड 10 एवं बलौदा वार्ड 13 में सहायिका पद हेतु 06 अगस्त 2025 तक आवेदन कार्यालयीन समय में सीधे अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदा से संपर्क किया जा सकता है।

बाल देखरेख संस्था में निवासरत बालकों को मिला परिवार

संस्था में निवासरत विगत एक वर्ष में अब तक कुल 10 बालकों को मिला पालन पोषण देखरेख परिवार

जांजगीर-चांपा कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल के मार्गदर्शन में संस्था में निवासरत विगत एक वर्ष में अब तक कुल 10 बालकों को पालन पोषण देखरेख परिवार से जोड़ा गया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल ने बताया कि 17 जुलाई 2025 जिले में संचालित बाल देखरेख संस्था हेल्प एण्ड हेल्पस समिति बाल गृह बालक जांजगीर में निवासरत 02 बालकों को पालन-पोषण देखेरख परिवार को नियमानुसार संरक्षण हेतु अस्थायी आदेश पर सपुर्द किया गया। परिवार द्वारा किये गये आवेदन के समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात सभी दस्तावेज सही पाये जाने पर बालक व परिवार का मैचिंग प्रक्रिया कराया गया। जहां बच्चों द्वारा परिवार के साथ रहने की इच्छा जाहिर किया गया एवं परिवार भी बालक को अपने साथ पालन-पोषण देखरेख हेतु ले जाने की सहमति पर संस्था में संरक्षण प्राप्त 02 बालकों को पालन-पोषण पारिवार को संरक्षण हेतु आदेश पारित किया गया। कार्यवाही में अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद शर्मा, सदस्य श्री तपोधन सिंह सिसोदिया, श्री देव प्रसाद बर्मन, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, श्रीमती आरती यादव सहित जिला बाल संरक्षण इकाई के समस्त स्टॉफविशेष सहयोग रहा।

अवैध दवा सप्लाई चैन और नकली उत्पादों पर कसी नकेल, राज्य भर के 170 संस्थानों में मारे गए छापे

हेल्पलाइन नंबर +91-9340595097 पर नकली औषधियों, प्रसाधन सामग्री या नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की दे सकते हैं जानकारी

अवैध दवा सप्लाई चैन और नकली उत्पादों पर कसी नकेल, राज्य भर के 170 संस्थानों में मारे गए छापे

रायपुर, लोकशक्ति

अवैध रूप से संचालित फर्मों, नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला और बाजार में बिक रही नकली प्रसाधन सामग्री से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को प्रदेश स्तर पर एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में औषधि निरीक्षकों की टीमों ने सघन छापेमारी के साथ ही कार्रवाई की है।

रायपुर जिले में ड्रग विभाग की टीम द्वारा भाटागांव स्थित लक्ष्मी इंटरप्राइजेज पर छापा मारते हुए बिना अनुज्ञप्ति के निर्माण हो रहे फिनाइल और हैण्डवाश उत्पादों (कुल कीमत 4.5 लाख) को जब्त किया गया। इसी प्रकार गुढ़ियारी स्थित शोला इंडस्ट्रीज में भी बिना लाइसेंस साबुन और हैंडवॉश निर्माण की गतिविधियों पर छापेमारी कर कच्चा माल, कंटेनर, लेबलिंग और

पैकेजिंग सामग्री (लगभग 2 लाख) जब्त की गई।

डूमरतराई स्थित औषधि वाटिका में ड्रग विभाग द्वारा नशीली दवाओं की जांच की गई, जहां मेसर्स वेनोर में नारकोटिक दवाओं के रिकॉर्ड और रजिस्टर में अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण के दौरान कुछ फर्जी प्रिस्क्रिप्शन भी बरामद हुए, जिसके आधार पर संबंधित फर्म को नोटिस जारी किया गया है।

बिलासपुर जिले के तेलीपारा स्थित मेसर्स आकाश बैंगल्स एंड कास्मेटिक में बिना लाइसेंस औषधियों का संधारण पाया गया, जहां से ?30,000 मूल्य की औषधियां जब्त कर कार्यवाही की गई। इसी क्षेत्र के तेलीपारा एवं व्यापार विहार की कास्मेटिक दुकानों से 5 नमूने लिए गए। रायगढ़ जिले के रोज लाइफ पुरानी हटरी में भी बिना लाइसेंस बिक रही औषधियों पर कार्यवाही की गई। वहीं धमतरी के भटगांव में धनेश्वर देवांगन के क्लिनिक से एलोपैथिक दवाओं को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की गई। मुंगेली जिले के प्रकाश मेडिकल एजेंसीज में आयुर्वेदिक दवाओं में एलोपैथिक दवाओं की मिलावट की आशंका के आधार पर टेबलेट का नमूना लिया गया और शेष स्टॉक को फॉर्म-15 में रोका गया। इसी प्रकार कबीरधाम जिले में शिव हर्बल एजेंसीज एवं विश्वमात्र आयुर्वेदिक चिकित्सालय से भी नमूना संग्रहण किया गया।

जांजगीर-चांपा जिले के महेश मेडिकल, सुभाष मेडिकल, अशोक मेडिकल, अरविन्द मेडिकल, आर.के. मेडिकल, अनिल मेडिकल, सोंकेसरिया मेडिकल, कृष्णा मेडिकल आदि में नारकोटिक दवाओं के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड में अनियमितताएं पाई गईं। जिनके विरुद्ध फॉर्म-35 में कार्यवाही दर्ज कर नोटिस जारी किया जा रहा है। जशपुर व कांकेर जिलों में भी ऐसी ही जांचें की गईं। बेमेतरा जिले के शिवम् जनरल स्टोर एवं मेहनलाल मांगीलाल राठी किराना दुकान में कास्मेटिक उत्पादों के बिल प्रस्तुत न कर पाने पर उत्पादों को फॉर्म-15 में दर्ज कर बिक्री से रोका गया।

आम जनता द्वारा नकली कास्मेटिक उत्पादों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के विभिन्न बाजारों में छापेमारी की गई। कुल 48 कास्मेटिक उत्पादों जैसे साबुन, हेयर ऑयल, बेबी लोशन, शैम्पू, फेयरनेस क्रीम, टेलकम पाउडर, शेविंग क्रीम, हेयर डाई आदि के विधिवत नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इस अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में तैनात कुल 78 औषधि निरीक्षकों की टीम ने 170 संस्थानों में छापेमारी कर आवश्यक नमूने एकत्रित किए और नियमानुसार कार्यवाही की।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि आमजन को नकली औषधियों और प्रसाधन सामग्रियों के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखा जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनमानस से अपील है कि नकली औषधियों, प्रसाधन सामग्री या नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी हेल्पलाइन नंबर +91-9340595097 पर अवश्य दें।

खास खबर

प्राचार्य पदोन्नति पर लगी रोक हटाने सुनवाई 23 को

कोरबा, (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा ने राज्य शासन से स्कूल शिक्षा विभाग में पिछले 12 वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने की मांग की है। मोर्चा के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा 1 जुलाई 2025 को पदोन्नति पर लगी रोक हटाने के बावजूद एकल पीठ में मामला लंबित है, जिसकी सुनवाई 23 जुलाई को होनी है।

30 जुलाई से पहले काउंसलिंग और पदस्थापना आदेश की मांग

संघर्ष मोर्चा ने स्कूल शिक्षा सचिव एवं लोक शिक्षण संचालक से अपील की है कि 30 जुलाई 2025 के पूर्व टी एवं ई संवर्ग के रिक्त प्राचार्य पदों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर पदस्थापना आदेश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रतिमाह लगभग 150-200 वरिष्ठ व्याख्याता व प्रधान पाठक बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो दुरूखद है।प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्राचार्यविहीन विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध काउंसलिंग से योग्य अधिकारियों को अंतिम सेवाकाल में पदोन्नति का लाभ मिलेगा और विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। संघर्ष मोर्चा ने प्रतीक्षा सूची से वरिष्ठ पात्रों को पदोन्नति सूची में शामिल करने की भी मांग रखी है।

रेत से लदा टिप्पर का टायर फटा, मची अफरा-तफरी, बाल-बाल बचे लोग

कोरबा, शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब निहारिका टॉकीज के समीप रेत से लदा एक टिप्पर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। टायर फटने की तेज आवाज से आसपास खड़े लोग और राहगीर घबरा गए और जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।

घटना स्थल के पास मौजूद लोगों ने बताया कि गायत्री मेडिकल के सामने एक टिप्पर खड़ा था, जिसमें रेत भरी हुई थी। रेत पूरी तरह गीली थी और उससे लगातार पानी टपक रहा था। जिससे यह स्पष्ट हो गया कि रेत हाल ही में नदी से निकाली गई है, और यह मामला रेत की तस्करी से जुड़ा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही टिप्पर निहारिका टॉकीज के समीप पहुंचा, उसका टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस अप्रत्याशित घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है और किसी अनहोनी की आशंका से इधर-उधर दौड़ने लगे

शिक्षकों की समस्याएं करने होगा काम : दयाल

कोरबा, पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में नव नियुक्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी के आर दयाल का शिक्षकों ने सौजन्य भेंट स्वागत कियाक्षेत्र में शिक्षा की वर्तमान स्थिति, समस्याएं और उसके निराकरण के उपायों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। शिक्षकों ने दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों की समस्याओं, शिक्षक संसाधनों की कमी, विद्यार्थियों की उपस्थिति, आधारभूत सुविधाओं की स्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर अपने सुझाव रखे।

न्याय प्रदान करना न्यायिक प्रणाली का एक हिस्सा है : न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा

बिलासपुर लोकशक्ति

। 21 को न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जिला राजनांदगाँव के बाह्य न्यायालय अंबागढ़ चौकी में पदस्थ न्यायिक कर्मचारीगण को बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने एवं न्यायिक बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिये आवास निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया गया । इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधीश, जिला राजनांदगाँव वर्चुअल माध्यम से तथा अन्य माननीय न्यायाधीशगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की वर्चुअल लिंक के माध्यम से गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने प्रभावशाली उद्बोधन में व्यक्त किया कि न्याय प्रदान करना न्यायिक प्रणाली का एक हिस्सा है, लेकिन साथ ही हमें ऐसा माहौल बनाना होगा कि, न्याय प्रणाली से जुड़े हर व्यक्ति को स्वच्छ एवं उचित कार्य-वातावरण प्राप्त हो, किसी भी संस्थान में अधोसंरचना का निर्माण और विकास उस संस्थान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते हैं। न्यायिक कर्मचारी, न्यायपालिका के आधार स्तंभ हैं, जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ न्यायिक व्यवस्था में योगदान देते हैं, उनका परिवार भी इस कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ इसमें सहयोग करता है। आवास व्यवस्था उपलब्ध होने से कर्मचारियों को व्यवहारिक एवं मानसिक संबल मिलने से कार्यक्षमता में वृद्धि होगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा यह विशेष रूप से व्यक्त किया गया कि छत्तीसगढ़ की समस्त जिला न्यायापालिका को सर्वोत्तम अधोसंरचना प्रदान करने हेतु उच्च न्यायालय प्रतिबद्ध है। जिला एवं बाह्य न्यायपालिका के पक्षकार, अधिवक्तागण, न्यायालयीन अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को बेहतर सुविधायुक्त एवं आधुनिक अधोसंरचना प्राप्त होने से बेहतर कार्य-वातावरण निर्मित होगा एवं न्यायिक प्रक्रिया में तेजी के साथ उच्च गुणवत्तायुक्त न्याय सुविधापूर्वक सुलभ हो सकेगा।

इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा कर्मचारियों के आवास को उच्च गुणवत्तायुक्त एवं आधुनिक संसाधनों के अनुसार तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसे अन्य जिलों में मॉडल के रूप में स्वीकार किया जा सके, साथ ही सिविल कोर्ट स्टॉफके सभी सदस्यों को बधाई देते हुये कहा कि आवास निर्माण पूर्ण होने पर आधिपत्य प्राप्त करने के पश्चात् वे परिसर को स्वच्छ रखें और उसमें दी गई मूलभूत सुविधाओं को नष्ट न करें, जिससे पश्चातवर्ती कर्मचारियों को भी उचित एवं सुविधायुक्त आवास का लाभ प्राप्त हो सके।

यह उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा पद भार ग्रहण करने के पश्चात् सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के दूरस्थ जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालयों का भ्रमण कर न्यायिक अधोसंरचना एवं आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने से पक्षकारों, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी एवं अधिकारियों को होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये दूरदर्शिता पूर्ण एवं सकारात्मक सोच के भागीरथ प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में न्यायिक अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास का कार्य हो रहा है, जिससे अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने के साथ पक्षकारों को सुविधायुक्त वातावरण शीघ्र न्याय प्राप्त करने की परिकल्पना साकार हो रही है।

उपरोक्त भूमिपूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम की शुरूआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगाँव के स्वागत भाषण से हुई और समापन जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबागढ़-चौकी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत रोपे गए पौधे

0-वन विकास निगम के अध्यक्ष पूर्वगृह मंत्री रामसेवक पैकरा हुए शामिल

0-20 हेक्टेयर क्षेत्र में 50000 पौधे लगाने का लक्ष्य

कोरबा, एनटीपीसी-कोरबा के सौजन्य से छ.ग. राज्य वन विकास निगम के औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल ने एनटीपीसी चारपारा राखड़बांध में ष्एक पेड़ माँ के नामष् अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में वन विकास निगम रायपुर के अध्यक्ष पूर्व गृहमंत्री राम सेवक पैकरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, अन्य अतिथियों में कोरबा नगर निगम महापौर संजू देवी राजपूत, निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, कोरबा वन मंडल के एसडीओ आशीष खैरवार, वन विकास निगम कोरबा के मंडल प्रबंधक दिवाकर पाठक सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने ष्एक पेड़ माँ के नामष् अभियान के तहत पौधरोपित किया और हरियाली की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दिया।

प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन : शिक्षिका और उसके बेटे के खिलाफ FIR

बिलासपुर

बिलासपुर में एक शिक्षिका और उसके बेटे के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। सरकंडा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया है। महिला शिक्षिका का नाम अरूंधति साहू और उनके बेटे का नाम साकेत साहू है।

दरअसल, सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित गीतांजलि सिटी में रविवार के दिन एक शिक्षिका के घर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था। इस आयोजन में 20 से 25 बच्चे शामिल हुए थे। आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन के लिए ब्रेनवाश किया जा रहा था। सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के लोग शिक्षिका के घर पहुंच गए और जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं और प्रार्थना सभा के आयोजकों में तीखी झड़प हुई।

इधर, सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। किसी तरह दोनों पक्षों को शांत करवा कर थाने लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार

प्रार्थना सभा का आयोजन शिक्षिका अरुंधति साहू के मकान में किया गया था। शिक्षिका कहां पदस्थ है और उनका खुद का मकान था या फिर किराए का मकान था इस बात की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दो लोगों पर अपराध दर्ज किया है। आगे इस मामले में शामिल लोगों की जांच में पुलिस जुटी है।

आंदोलन को मजबूर तहसीलदार : 17 मांगों पर 26 तक अल्टीमेटम

28 से चरणबद्ध आन्दोलन

कहा-पूरा सेटअप दें या लोक सेवा गारंटी की समय सीमा से मुक्त करें

कोरबा, जिले का राजस्व विभाग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। संसाधनों के अभाव में तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका निराकरण के लिए अब ये आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। संसाधन नहीं तो काम नहीं सिद्धांत पर आधारित 17 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु 26 जुलाई तक सकारात्मक पहल नहीं होने की स्थिति में 28 जुलाई से प्रस्तावित चरणबद्ध आंदोलन की सूचना कलेक्टर के माध्यम से शासन को प्रेषित की गई है। बताया गया कि छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा पूर्व में भी विभाग एवं शासन को समय-समय पर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया है। विशेष रूप से तहसील कार्यालयों में पदस्थ तहसीलदारों को संसाधनों की अत्यंत कमी, मानवीय संसाधन, तकनीकी सुविधाएं, सुरक्षा, शासकीय वाहन एवं प्रशासनिक सहयोग की अनुपलब्धता से कार्य निष्पादन में गंभीर कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही हैंइन विषयों को लेकर संघ द्वारा अनेक अवसरों पर ज्ञापन प्रस्तुत कर मांगों के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है। यह आशा की जाती रही है कि शासन इन विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक एवं प्राथमिकता के साथ विचार करेगा। कहा गया है कि यदि दिनांक 26 जुलाई 2025 तक इस दिशा में कोई स्पष्ट एवं सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो संघ के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार निम्नानुसार चरणबद्ध आंदोलन हेतु विवश होंगे।

सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत, 8 साल से बस्ती में रहकर कर रहा था मजदूरी

कोरबा, लोकशक्ति।

उरगा-चांपा मार्ग पर शुक्रवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक को सिर और सीने पर गंभीर चोटें आईं। हादसे की जानकारी मिलने पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वाहन चालक की तलाश की जा रही है। हादसे की यह घटना मड़वारानी के पास की बताई जा रही है। मृतक युवक की पहचान पीलू सहिस के रूप में हुई है। पीलू पिछले 8 सालों से चांपा रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक बस्ती में रह रहा था। उसकी पहचान करने वाली पूनम सहिस ने बताया कि लगभग 15 साल पहले यह बालक मात्र 8 साल की उम्र में चांपा स्टेशन के पास भटकता हुआ मिला था। बस्तीवासियों ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछताछ की, लेकिन वह कुछ नहीं बता पाया। बस्तीवालों ने उसे 'पीलू' नाम दिया और तब से वह वहीं रहकर मजदूरी कर अपने जीवनयापन करता था। वह सरल स्वभाव का था और सभी की मदद करता था। बस्ती के हर घर में उसे भोजन मिल जाता था। वह रोज सुबह काम पर निकलता और देर शाम लौटता था।

शुक्रवार की रात जब पीलू देर तक घर नहीं लौटा, तो बस्ती के लोगों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। उसी दौरान एक वाहन चालक से उन्हें हादसे की जानकारी मिली। बाद में वे लोग मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां मॉर्च्युरी में पीलू का शव मिला।

आंदोलन को मजबूर तहसीलदार : 17 मांगों पर 26 तक अल्टीमेटम, 28 से चरणबद्ध आन्दोलन

कहा-पूरा सेटअप दें या लोक सेवा गारंटी की समय सीमा से मुक्त करें

कोरबा, । जिले का राजस्व विभाग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। संसाधनों के अभाव में तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका निराकरण के लिए अब ये आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। संसाधन नहीं तो काम नहीं सिद्धांत पर आधारित 17 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु 26 जुलाई तक सकारात्मक पहल नहीं होने की स्थिति में 28 जुलाई से प्रस्तावित चरणबद्ध आंदोलन की सूचना कलेक्टर के माध्यम से शासन को प्रेषित की गई है। बताया गया कि छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा पूर्व में भी विभाग एवं शासन को समय-समय पर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया है। विशेष रूप से तहसील कार्यालयों में पदस्थ तहसीलदारों को संसाधनों की अत्यंत कमी, मानवीय संसाधन, तकनीकी सुविधाएं, सुरक्षा, शासकीय वाहन एवं प्रशासनिक सहयोग की अनुपलब्धता से कार्य निष्पादन में गंभीर कठिनाईयाँ उत्पन्न हो रही हैंइन विषयों को लेकर संघ द्वारा अनेक अवसरों पर ज्ञापन प्रस्तुत कर मांगों के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है। यह आशा की जाती रही है कि शासन इन विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक एवं प्राथमिकता के साथ विचार करेगा। कहा गया है कि यदि दिनांक 26 जुलाई 2025 तक इस दिशा में कोई स्पष्ट एवं सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो संघ के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार निम्नानुसार चरणबद्ध आंदोलन हेतु विवश होंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रजक युवा गाडगे सम्मेलन में शामिल हुए

धोबी समाज के विकास में रजककार बोर्ड की अहम भूमिका

बिलासपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित रजक युवा गाडगे सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने महापुरूष संत गाडगे की पूजा अर्चना कर राज्य स्तरीय गाडगे सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री साय ने रजक समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं,प्रबुद्धजनों और समाजसेवियों को धोबी समाज की ओर शाल, श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। अध्यक्षता रजककार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस अवसर पर विधायक अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी,जिला अध्यक्ष दीपक सिंह उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि की आसंदी से मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रजक समाज का सामाजिक सद्भाव और सेवा भाव हमेशा से अनुकरणीय रहा है। छत्तीसगढ़ के हर गांव में इस समाज की मौजूदगी है। गांव में शादी-विवाह, छठ्ठी सहित अन्य सनातनी परम्पराएं इनके सहयोग के बगैर संपन्न नहीं होती। उनके पुश्तैनी व्यवसाय के विकास के लिए

राज्य सरकार ने रजककार विकास बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड के जरिए उन्हें पुश्तैनी धंधा के विकास के लिए किफायती दर पर लोन सुविधा मुहैया कराया जायेगा। समाज के युवाओं को और बुलंदियों पर ले जाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास करेगी।

श्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें अलग छत्तीसगढ़ राज्य दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के 15 साल के कार्य-काल में राज्य ने काफी तरक्की की। इसके पहले लोगों को भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन डॉ0 सिंह के प्रयासों से लोगों को भुखमरी की समस्या से निजात मिली। उन्होंने कहा कि मोदी की गारण्टी के रूप में राज्य सरकार किये गये अपने हर वादे को पूरा कर रही है। हमने 3100 रूपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी किया। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को हर महीने एक-एक हजार रूपए दे रहे हैं। तेन्दूपत्ता की खरीदी 5500 रूपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से किया जा रहा है। रामलला एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी हमने शुरू की है। सुशासन लाने और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करने के लिए अभिसरण विभाग गठित किया गया है। सभी तरह के काम ऑनलाईन होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगा हैं।

श्री साय ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारी सरकार का मूलमंत्र है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय विजन में हमारे छत्तीसगढ़ का विशेष योगदान होगा। हमने भी राष्ट्रीय विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेन्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है। इस नीति में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग लोगों को उद्योग एवं रोजगार के साधन निर्मित करने में खासा तवज्जो दिया गया है। उद्योग नीति से आकर्षित होकर पिछले छह-आठ महीने में साढ़े 6 लाख के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। हमने राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार भी खोल दिए हैं। डेढ़ साल में लगभग 10 हजार सरकारी नौकरी युवाओं को दिए हैं। जल्द ही 5 हजार शिक्षक भर्ती के विज्ञापन निकलने वाले हैं। सरकारी नौकरी के इतर भी स्वरोजगार के लिए अच्छा माहौल बना है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के जरिए ही हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सपने को पूरा करने में मदद मिलती है। शिक्षा से ही रोजगार के अवसर खुलते हैं।

सीएमएचओ ने शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण

0 सेवाओं में सुधार के दिए निर्देश

कोरबा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केशरी द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) ढोढ़ीपारा, हमर क्लीनिक पथर्रीपारा एवं रिसदी स्वास्थ्य केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, प्रसव कक्ष, दवा भंडार, पैथोलॉजी सहित विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की एवं दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान सीएमएचओ ने पाई गई कमियों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डॉ. केशरी ने विशेष रूप से निर्देशित किया कि वर्षा ऋतु में बढ़ने वाली मौसमी बीमारियों एवं सर्पदंश के इलाज हेतु सभी आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ढोढ़ीपारा स्वास्थ्य केन्द्र में लक्ष्य अनुरूप संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने एवं सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में 100 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर उपस्थिति दर्ज करने और बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने की सख्त हिदायत दी।

दोहा –संग्रह 'प्रीत मिलेगी राह का हुआ विमोचन

रायपुर । राजधानी रायपुर के वृन्दावन सभागार में कल 19 जुलाई को आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम में राजेश जैन 'राही' की 15 वीं पुस्तक 'प्रीत मिलेगी राह में' (श्रृंगार दोहा संग्रह) का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि डॉ वर्णिका शर्मा,अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. माणिक विश्वकर्मा 'नवरंग' सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी इंद्रनाथ सिंह, वरिष्ठ साहित्यकार सुरेंद्र रावल, डॉ जे.के. डागर विद्यासागर, सुप्रसिद्ध कवयित्री द्वय श्रीमती शकुंतला तरार और डॉ. सीमा श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक का विमोचन किया। विमोचित दोहा संग्रह पर डॉ.माणिक विश्वकर्मा 'नवरंग' ने कृति पर अपने विचार व्यक्त किए । उन्होंने और मुख्य अतिथि डॉ. वर्णिका शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने दोहा -संग्रह के प्रकाशन पर कवि राजेश जैन 'राही ' को बधाई दी.कार्यक्रम की अध्यक्षता सुविख्यात ग़ज़ल गायक राजेश सिंह (सेवानिवृत्त भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी) ने की। युवा संस्था के संस्थापक एम.राजीव और डॉ. महेंद्र ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ.वर्णिका शर्मा (अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग) का अभिनंदन कर उन्हें नवरंग समाज रत्न सम्मान से सम्मनित किया गया। अभिनंदन पत्र का वाचन सुयोगिता साहू ने किया। मंच संचालन डॉ. सीमा श्रीवास्तव और राजेश जैन 'राही' ने किया।कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक रचनाकार शामिल हुए। इस अवसर पर कवियों को 'कुछ बादल -कुछ धूप' विषय देकर उस पर काव्य रचना के लिए प्रेरित किया गया। बरसात के झमाझम मौसम में कविताओं, गीतों और ग़ज़लों की बारिश वृंदावन सभागार में होती रही। कार्यक्रम का संचालन करते हुए राजेश जैन 'राही' ने अपने कुछ दोहे भी सुनाए। प्रतिष्ठित ग़ज़ल गायक राजेश सिंह ने अपने गायन से समां बांध दिया।सुअंजनी अग्रवाल ने राजेश जैन 'राही' के दोहों का सस्वर गायन किया।

जनसंपर्क दिवस पर, राष्ट्रीय पीआर कॉनक्लेव का आयोजन

कनेक्टकॉन-2025' में जनसंपर्क की नई चुनौतियों और अवसरों पर राष्ट्रीय मंथन

रायपुर । जनसंपर्क दिवस पर बीएसपी के जनसंपर्क विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पीआर कॉनक्लेव का आयोजन कियाग या। जिसका उद्देश्य कनेक्ट कम्युनिक्रि येट चीन पर आधारित था। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कान्क्लेव को कनेक्टकॉन 2025 का दर्जा दिया गया। पीआईबी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सेल भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के जनसंपर्क विभाग ने विश्व जनसंपर्क दिवस के अवसर पर शुक्रवार को भिलाई निवास में राष्ट्र स्तरीय पीआर कॉन्क्लेव 'कनेक्टकॉनङ्क2025' का आयोजन किया। 'कनेक्ट. कम्युनिकेट. क्रिएट.' थीम पर आधारित इस एकदिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री चितरंजन महापात्र ने कार्यपालक निदेशकों के साथ दीप प्रज्वलन कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जनसंपर्क अब केवल प्रेस ब्रीफिंग तक सीमित न रहकर संस्थागत विकास का रणनीतिक आधार बन चुका है। उन्होंने भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प और इस्पात उद्योग की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।कार्यक्रम में राउरकेला, बोकारो, कॉर्पोरेट कार्यालय, वीआईएसएल, सीएफ्री सहित भारतीय स्टेट बैंक और एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री अमूल्य प्रियदर्शी ने स्वागत भाषण में आयोजन का उद्देश्य और सत्रों का परिचय दिया।

वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय संकल्प में छत्तीसगढ़ की भूमिका महत्वपूर्ण– मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर । शिक्षा ही वह साधन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। शिक्षा से ही रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारी सरकार का मूलमंत्र है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय संकल्प में छत्तीसगढ़ की महत्त्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित है। हमने राष्ट्रीय विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ विजन डॉक्युमेंट भी जारी किया है, और उसके प्रत्येक बिंदु को धरातल पर उतारने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित रजक युवा गाडगे सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने संत गाडगे महाराज की पूजा-अर्चना कर राज्य स्तरीय गाडगे सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने सम्मेलन में रजक समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं, प्रबुद्धजनों एवं समाजसेवियों को शाल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि रजक समाज का सामाजिक समरसता और सेवा भाव हमेशा से अनुकरणीय रहा है।छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में इस समाज की उपस्थिति है, और शादी-विवाह, छठ्ठी सहित अन्य सनातन परंपराएं इनके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं होतीं। इनके पुश्तैनी व्यवसाय के सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार ने रजककार विकास बोर्ड का गठन किया है, जिसके माध्यम से उन्हें किफायती दर पर ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज के युवाओं को उन्नति के नए आयाम तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सुशासन की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। आज अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन मोड में संचालित की जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त हुई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्येक गारंटी को वचनबद्धता के साथ पूर्ण कर रही है। हमने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। तेन्दूपत्ता की खरीदी 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के माध्यम से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दिव्यांगजनों को रोजगार एवं उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। नई उद्योग नीति से आकर्षित होकर बीते छह से आठ महीनों में लगभग साढ़े छह लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर सृजित किए हैं।

स्किल इंडिया मिशन ने देश की तस्वीर बदली, अब छत्तीसगढ़ बना रहा है नया इतिहासः मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ को स्किल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहलः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा समाज के हर वर्ग की भागीदारी से ही बनेगा विकसित छत्तीसगढ़

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हम विकसित भारतविकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्यरत हैं, और इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। मुख्यमंत्री साय आज भिलाई स्थित रूंगटा यूनिवर्सिटी में आयोजित विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह आयोजन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा। गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने 8183 प्रतिभागियों को एक सप्ताह के भीतर दिए गए प्रशिक्षण को प्रमाणित किया है और संस्थान को इसका प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उन्होंने रूंगटा यूनिवर्सिटी प्रबंधन को इस निःशुल्क और अभूतपूर्व आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर एवं दक्ष बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भिलाई को इस्पात नगरी के साथ-साथ मिनी इंडिया भी कहा जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में रूंगटा यूनिवर्सिटी का योगदान अत्यंत सराहनीय है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने विगत 25 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और इस वर्ष को हम राज्य की रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार हुआ और वर्तमान में राज्य में 15 मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, सिपेट, एम्स, और लॉ यूनिवर्सिटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में राज्य सरकार ने समान रूप से उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। बीते डेढ़ वर्षों में सुशासन की स्थापना के लिए ठोस प्रयास हुए हैं। शासन को पारदर्शी बनाने हेतु अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध प्रदेश है और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। जब यह मिशन प्रारंभ हुआ था, भारत विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था था – और आज, केवल एक दशक में भारत चौथे स्थान पर पहुँच चुका है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मेगा प्लेसमेंट कैंप्स के माध्यम से नियोक्ताओं और प्रशिक्षित युवाओं के बीच संतुलन स्थापित हुआ है। यह कार्य डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को बेहद उपयोगी बताते हुए कहा कि यह योजना युवाओं के लिए अनुभव के साथ-साथ आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, जिससे उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति में युवाओं के लिए विशेष अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। एक हजार से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को अनुदान देने का प्रावधान है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त रियायतें दी गई हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर के सभी 32 विकासखंडों में स्किल इंडिया मिशन की गतिविधियाँ आरंभ हो चुकी हैं।उन्होंने कहा कि ईज ऑफडूइंग बिजनेस और ईज ऑफलिविंग को प्रोत्साहन देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगों को क्लीयरेंस की प्रक्रिया को अत्यंत सरल बनाया गया है। इससे राज्य में निवेश को गति मिली है। अब तक 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके अनुमोदन की प्रक्रिया प्रगति पर है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हाल ही में नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल कंपनी का शुभारंभ हुआ है। यह दो कारणों से संभव हुआ–एक, नवा रायपुर को फार्मा हब के रूप में विकसित किया गया है, और दूसरा, फार्मा उद्योग के लिए नई नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास हाल ही में किया गया है। इसके पीछे एआई और आईटी क्षेत्र में निवेश हेतु विशेष अनुदान का योगदान है।छत्तीसगढ़ सरकार ने देश का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क भी नवा रायपुर में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने निजी संस्थानों, विशेषकर रूंगटा यूनिवर्सिटी की सराहना करते हुए कहा कि वे राज्य सरकार के प्रयासों में पूर्ण सहभागी बनकर छत्तीसगढ़ को स्किल हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिभागियों और यूनिवर्सिटी परिवार को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। उल्लेखनीय है कि भिलाई स्थित रूंगटा यूनिवर्सिटी में आयोजित विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ को स्किल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया।

अलग–अलग क्षेत्र से दो दोपहिया वाहन पार

रायपुर । शहर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्र से अज्ञात चोर ने दो दोपहिया वाहन पार कर दिया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में ब्राम्हणपारा निवासी सूरज शर्मा 25 वर्ष ने कोतवाली थाना में शिकायत किया कि वह अपनी एक्टिवा क्रमांक सीजी 04 एचटी 8066 को दानी गर्ल्स स्कूल के पीछे खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए एक्टिवा की कीमत करीब 15 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है।

गांजा के साथ दो युवक गिरफ्तार

रायपुर । गंज थाना पुलिस ने होटल उदय दीप के कमरा में दबिश देकर गांजा के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 48 किलो 360 ग्राम गांजा जब्त किया है।

मिली जानकारी के अनुसार गंज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन स्थित होटल उदय दीप के कमरा नंबर 205 में दबिश देकर आरोपी विनोद गुप्ता 32 वर्ष और दीनेश गुप्ता 32 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों के पास से 4 बैग में रखे 48 किलो 360 ग्राम गांजा जब्त किया है। जिसकी कीमत करीब 4 लाख 83 हजार 600 रुपए के आसपास बताई जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी नवलीन को बधाई - कहा,

छत्तीसगढ़ की उभरती प्रतिभा को मिलेगा हरसंभव सहयोग

महासमुंद की नवलीन कौर ने तीरंदाजी में नेशनल गेम्स में बनाया स्थान, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीता था गोल्ड मेडल

रायपुर। खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के हर खिलाड़ी को उसकी मेहनत, लगन और क्षमता के अनुरूप अवसर, संसाधन और मंच उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने महासमुंद जिले की नवोदित तीरंदाज नवलीन कौर को आगामी राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में स्थान बनाने पर बधाई और शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवलीन जैसी खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के भविष्य की नींव हैं और सरकार उन्हें खेल के हर स्तर पर निखारने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

जन्म से ही स्वास्थ्यगत चुनौतियों से जूझने वाली नवलीन ने इसे अपनी कमज़ोरी नहीं, बल्कि ताकत में बदल दिया और खेल को अपना जीवन-मार्ग चुना। उन्होंने फरवरी 2025 में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि इच्छाशक्ति और मेहनत के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।

महासमुंद जिले के बागबाहरा की निवासी नवलीन कौर, श्री अरविंद एवं श्रीमती रंजीत कौर छाबड़ा की सुपुत्री हैं। उनका जन्म गर्भावस्था के सातवें महीने में हुआ था, जिससे प्रारंभिक वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियाँ रहीं। आस-पड़ोस, रिश्तेदार और परिचित हमेशा उनकी तबीयत के बारे में पूछते रहते थे, जिससे वह कभी-कभी उदास हो जाती थीं। लेकिन नवलीन ने इस जिज्ञासा को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और खुद को एक नई दिशा में ढाल दिया।

वर्ष 2018 में नवलीन ने बागबाहरा से लगभग पांच किलोमीटर दूर स्थित बिहाझर बालाश्रम में तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्रारंभ किया। वे महासमुंद जिले की पहली महिला तीरंदाज बनीं। स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने दो बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए और एक बार राष्ट्रीय स्तर की स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में चौथा स्थान अर्जित किया। वर्ष 2023 में उन्होंने गुजरात में आयोजित एफजीएफआई राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया और राज्य स्तरीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

छत्तीसगढ़ के साहित्यकार पयोधि भोपाल में हुए सम्मानित विभिन्न विधाओं की 56 पुस्तकों के रचनाकार हैं पयोधि

रायपुर । वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मीनारायण पयोधि को कल रविवार 20 जुलाई को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय जीवन शैली समारोह में सम्मानित किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश सरकार के खेल, युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग थे. उन्होंने पयोधि को 'जगदीश गुरु साहित्यकार सम्मान 'से अलंकृत किया. विभिन्न विधाओं में पयोधि की 56 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं.उल्लेखनीय है कि पयोधि मूल रूप से छत्तीसगढ़ के भोपालपटनम के निवासी हैं. साहित्य भारती छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री बलदाऊ राम साहू ने बताया कि सम्मान समारोह डॉ.गांगुली योग विद्यापीठ, भोपाल द्वारा कमला पार्क भोपाल स्थित आचार्य नरेन्द्रदेव पुस्तकालय में आयोजित किया गया. साहित्यकार श्री पयोधि को यह सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उनकी लगातार सृजन -सक्रियता और विशेष उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया. उन्होंने भोपाल (मध्यप्रदेश) में वर्ष 1990 से 1997 तक आदिम जाति विकास विभाग के वन्या प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका'समझ-झरोखा' का सम्पादन किया और बाद में आदिम जाति अनुसंधान संस्थान (ट्रायबल रिसर्च इंस्टिट्यूट)में भी अपनी सेवाएँ दी.इस दौरान भी उनकी साहित्य -साधना निरंतर जारी रही.श्री पयोधि वन्या प्रकाशन में सहायक सम्पादक के पद से वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त हुए.इन दिनों वे भोपाल में रहकर साहित्य-साधना में लगे हुए हैं. वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त होने बाद उन्होंने 2022 तक वन्या प्रकाशन में विशेषज्ञ-सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी.

मिठाईयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिए निर्देश

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मिठाईयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिए निर्देश

रायपुर। त्योहारी सीजन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने चलाया जांच अभियान आगामी दिनों में रक्षाबंधन सहित कई त्यौहार आने वाले हैं। त्यौहारी सीजन में मिठाईयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में सिमगा एवं भाटापारा के कई दुकानों में भी खाद्य पदार्थों की जांच की गई।

खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों के होटल का निरीक्षण किया गया। सिमगा स्थित बालाजी जोधपुर स्वीट्स से खोवा कतली एवं श्री कृष्णा डेयरी से पनीर का नमूना लिया गया।जांच के दौरान भाटापारा के ट्रांसपोर्ट ऑफिस एवं गैराज का भी निरीक्षण कर रिकॉर्ड खंगाला गया कि कोई अमानक या नियम विरुद्ध खाद्य पदार्थों का परिवहन तो नहीं हो रहा। जांच टीम के द्वारा बिना पक्का बिल व रसीद के खाद्य पदार्थ एवं मिठाइयों का ट्रांसपोर्ट नहीं करने की हिदायत दी गई है।

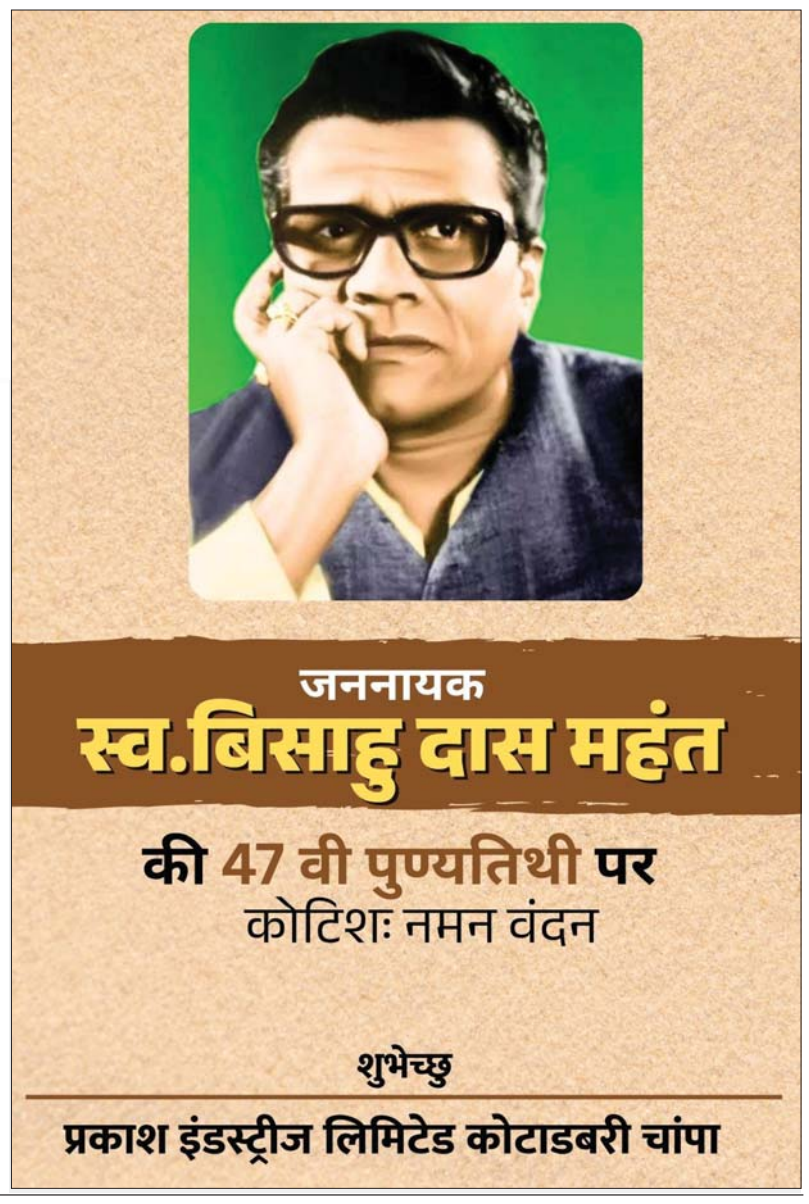

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाउस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)